अक्टूबर 2021

₹ 20

समाजवादी बुलेटिन

विजय पथ पर
विजय यात्रा 6

निजीकरण बेशुमार, आरक्षण पर वार 28

चलो सपा की ओर 68

लोकतंत्र के लिए जरूरी है जाति जनगणना 40

R.N.I. No. 68832/97

हर तरफ महंगाई और कुशासन का बोलबाला है। वर्तमान सरकार की इस बारे में कोई नीति नहीं। समाज में बराबरी लाने के बजाए विषमता की खाई को बढ़ाया जा रहा है। इन हालातों को बदलना जरूरी है। समाजवादी पार्टी शुरू से परिवर्तन की राजनीति करती रही है। इसमें नौजवानों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है।

मुलायम सिंह यादव

संस्थापक-संरक्षक, समाजवादी पार्टी

समाजवादी बुलेटिन
अक्टूबर 2021
वर्ष 22| संख्या 12

प्रिय पाठकों,
समाजवादी बुलेटिन आपकी अपनी पत्रिका है। इसके नए और बदले कलेवर को आप सबने सराहा है। आपका यह उत्साह वर्धन हमारी ऊर्जा है। कृपया अपनी राय से हमें अवगत कराते रहें। इसके लिए आप हमें नीचे दिए गए ईमेल पर लिख सकते हैं। कृपया अपना पूरा नाम, पता एवं मोबाइल नंबर जरूर दें। हम बुलेटिन को और बेहतर बनाने का प्रयास जारी रखेंगे। आपके संदेश की प्रतीक्षा रहेगी।
धन्यवाद

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक
प्रोफेसर रामगोपाल यादव
☎ 0522 - 2235454
samajwadibulletin19@gmail.com
bulletinsamajwadi@gmail.com
Mob:- 9598909095
/samajwadiparty

समाजवादी पार्टी के लिए
19, विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ से प्रकाशित
अवध पब्लिशिंग हाउस, 8 पान दरीबा, लखनऊ से मुद्रित
R.N.I. No. 68832/97

अंदर

यूपी में जंगलराज 46

06 कवर स्टोरी
विजय पथ पर विजय यात्रा

राजकाज 28
निजीकरण बेशुमार, आरक्षण पर वार

लोकतंत्र के लिए जरूरी है जाति जनगणना 40
चलो सपा की ओर 68

आजम साहब के खिलाफ राजनीतिक द्वेष बना बड़ा मुद्दा

बुलेटिन ब्यूरो

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं रामपुर के सांसद आजम खान साहब को भाजपा सरकार द्वारा साजिशन फंसाया जाना अब बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में समाज के हर वर्ग में फैले उनके समर्थकों को अदालत पर पूरा यकीन है। उनका मानना है कि कोर्ट में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा एवं आजम साहब बेदाग बरी होंगे।

उनके समर्थकों एवं समाजवादी पार्टी का मानना है कि अदालतों के अलावा जनता की अदालत भी आजम साहब के पक्ष में फैसला सुनाएगी। उनका कहना है कि आजम साहब के खिलाफ सत्ता के इशारे पर हो रही मनमानी दरअसल इस सरकार की जुल्मी मानसिकता की ही बानगी है। जिस तरह समाज के हर वर्ग को प्रताड़ित करने का काम इस सरकार ने किया है वैसा ही आजम साहब के खिलाफ भी किया जा रहा है क्योंकि वे न कभी जुल्म के सामने झुके और न ही समझौता किया।

आजम साहब के समर्थकों का मानना है कि प्रदेश में शीघ्र चुनाव होनेवाले हैं और इस सरकार की जनता के उत्पीड़न वाली

मानसिकता का हिसाब जनता अपने वोट से करेगी। जनता ने आजम साहब समेत तमाम अन्य लोगों के खिलाफ की गई उत्पीड़न की कार्रवाई का जवाब अपने वोट की ताकत से इस सरकार को विदा करने का मन बना लिया है। भाजपा सरकार के मनमाने रवैए से आम लोगों के बीच उपज रही नाराजगी चुनावी मुद्दा बन चुकी है।

उल्लेखनीय है कि श्री आजम खान प्रदेश के प्रतिष्ठित राजनेता हैं। वे 9 बार विधायक, 5 बार मंत्री और एक बार राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं। इस समय वह रामपुर से लोकसभा के सदस्य हैं। मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय जैसा उच्च शैक्षणिक संस्थान उन्हीं की देन है। ऐसी शख्सियत के खिलाफ सत्तारूढ़ पार्टी के कहने पर पुलिस-प्रशासन द्वारा की जा रही इस मनमानी कार्रवाई के खिलाफ समाजवादी पार्टी लगातार मुखर रही है।

खुद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने आजम साहब के खिलाफ हो रही मनमानी के मुद्दे पर लगातार सरकार को घेरा है। आजम साहब से मिलने वे न सिर्फ सीतापुर कारागार गए बल्कि उनकी बीमारी के दौरान लखनऊ के अस्पताल में उनके इलाज की अवधि में भी लगातार उनका हाल-चाल जानने के लिए जाते रहे।

आजम साहब की रिहाई की मांग करते हुए श्री अखिलेश यादव ने रामपुर में सपा की साइकिल यात्रा भी निकाली जिसमें खुद उन्होंने भी साइकिल चलाई।

श्री अखिलेश यादव कई अवसरों पर यह आरोप लगा चुके हैं कि आजम साहब के खिलाफ राजनीतिक द्वेष के तहत कार्रवाई की जा रही है और उन्हें तत्काल रिहा किया जाना चाहिए। श्री अखिलेश यादव ने आजम साहब के परिवारजनों के साथ लगातार संपर्क बना रखा है और कई अवसरों पर रामपुर जाकर उनसे मुलाकात भी की है। इधर हाल ही में मीडिया के सवालों के जवाब में आजम साहब की बहू सिदरा अदीब जी ने राजनीति से प्रेरित कुछ लोगों द्वारा लगाए जानेवाले आरोपों पर कहा कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश जी ने हमेशा पूरा साथ दिया है। पार्टी हमारे साथ है, हम अकेले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि अफसोस है कि इस समय पापा हम लोगों के बीच नहीं हैं, लेकिन उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द जेल से बाहर आकर हमारे बीच जरूर आएंगे। वे रामपुर के बड़े हैं, हमदर्द हैं, अभी के नहीं बल्कि 40 साल पुराने सियासतदां है। रामपुर वालों ने उन्हें कायदे मिल्लत तक कहा है।

गौरतलब है कि आजम खान साहब की रिहाई की मांग पर समाजवादी पार्टी लगातार मुखर होकर सड़क पर उतरती रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के निर्देश पर 15 जुलाई 2021 को हुए प्रदेश व्यापी प्रदर्शन कार्यक्रम में आजम खान साहब की रिहाई प्रमुख मांगों में शामिल थी। सपा की ओर से 15 जुलाई को हुए प्रदर्शन के बाद राज्यपाल के नाम संबोधित प्रशासन को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि प्रदेश सरकार आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को तत्काल रिहा करे। सपा नेताओं ने कहा कि वरिष्ठ नेता व सांसद आजम खान का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है। इसे देखते हुए उन्हें छूट दे देनी चाहिए, ताकि वह अपना इलाज सही तरीके से करा सकें।

रामपुर के नवनियुक्त सपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल ने हाल ही में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व आजम साहब की पत्नी व रामपुर की विधायक डॉ. तंज़ीन फ़ातिमा जी के घर जाकर मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया और कहा कि रामपुर में आजम खान साहब की प्रेरणा से पार्टी को और मजबूती दी जाएगी। उन्होंने खुद को मिली जिम्मेदारी के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, आजम खान साहब व डॉ. तंज़ीन फ़ातिमा जी को धन्यवाद ज्ञापित किया।

इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने हालिया फैसले में आजम खान साहब के बेटे अब्दुल्ला आजम खान को राहत देते हुए विधायकी खत्म करने के आदेश को चुनौती देने वाली उसकी याचिका को फिर बहाल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट अब मेरिट के आधार पर याचिका पर सुनवाई करेगी।अब्दुल्ला आजम खान भी सीतापुर कारागर में हैं। उन्हें समाजवादी पार्टी ने हाल में गठित नई प्रदेश कार्यकारिणी में भी जगह दी है। उन्हें सचिव बनाया गया है।

विजय पथ पर विजय यात्रा

उत्तर प्रदेश में बदलाव की बयार चल रही है और बयार को आंधी में बदलने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने विजय यात्रा की शुरुआत कर दी है। इस विजय यात्रा को पहले ही दिन से जिस तरह समाज के हर तबके का व्यापक जनसमर्थन मिल रहा है उससे स्पष्ट है कि प्रदेश की जनता ने श्री अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश की बागडोर सौंपने का फैसला कर लिया है। विजय यात्रा के पहले चरण से जो माहौल बना है वह संकेत है कि आने वाले दिनों में यात्रा के अगले चरणों में यह समाजवादी पार्टी के पक्ष में और मजबूत होता चला जाएगा। विजय यात्रा की शुरुआत, यात्रा मार्ग में आम लोगों के उत्साह और उससे बने माहौल पर पेश है ***दुष्यंत कबीर*** *की विस्तृत रिपोर्ट:*

जहां तक नजरें देख सकें वहां भीड़ ही भीड़। सड़क के दोनों ओर दौड़ते नौजवानों का रेला। सब हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए। सड़क किनारे खड़े बुज़ुर्ग। घरों के दरवाजों और छतों पर खड़ीं हर उम्र की महिलाएं। सभी की निगाहों में उत्साह, उमंग और उम्मीद की चमक! समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव की विजय यात्रा के पहले चरण के चार जनपदों में हर जगह यही माहौल था। वे जिधर से भी गुजरे समाज के हर तबके के लोगों ने उन्हें हाथों-हाथ लिया और यह साफ संदेश दिया कि उत्तर प्रदेश की जनता 2022 में बदलाव के लिए तैयार है।

समाजवादी विजय यात्रा में जनता के हर वर्ग से जो उत्साहपूर्ण और स्वतः स्फूर्त समर्थन मिला उसने प्रदेश की राजनीति में बड़ी हलचल पैदा कर दी है। इस यात्रा के जरिए श्री अखिलेश यादव ने 2022 में होने वाले चुनावों की निर्णायक शुरुआत कर दी है। विपक्ष में रहते हुए भी श्री अखिलेश यादव के प्रति युवाओं में विशेष आकर्षण है, उनके प्रति जो निष्ठा है, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण उमड़ते जनसैलाब में किसानों और गरीबों में आशा का संचार होने से स्पष्ट दिखा।

श्री अखिलेश यादव ने विजय यात्रा की शुरुआत 12 अक्टूबर को कानपुर के गंगा घाट से की। वे अपने समाजवादी विजय रथ से चार जिलों कानपुर शहर, कानपुर देहात,

हमीरपुर और जालौन पहुंचे। यात्रा मार्ग में हर जगह हजारों नौजवान उनके रथ के साथ-साथ दौड़े। अपने प्रिय नेता की एक झलक पाने को युवा इतने आतुर थे कि उन्हें धूप-गर्मी की भी परवाह नहीं थी। जगह-जगह लोग उनके स्वागत में खड़े थे।

समाजवादी विजय यात्रा के शुरुआती दौर से बने माहौल से ही प्रदेश में राजनीतिक क्षेत्रों को इस बात का आभास हो गया है कि कल का दिन ऊर्जावान युवा नेता अखिलेश जी का है। उनकी लोकप्रियता असीमित है। घर-बाहर सर्वत्र उनके प्रशंसक है। डाॅ. लोहिया, बाबा साहेब अम्बेडकर और चौधरी चरण सिंह के विचारों को सामने रखने के साथ ही उन्होंने आधुनिक युग के नए विजन को भी अपनाया है। जनता को साइकिल की रफ्तार पसंद है। उसके साथ उसकी उम्मीदें भी बंधी हैं। जनता को अब यह विश्वास हो चला है कि उनकी खुशहाली और तरक्की का हर सपना समाजवादी पार्टी के बहुमत में आने और श्री यादव के मुख्यमंत्री बनने से ही पूरा होगा।

12 अक्टूबर को श्री अखिलेश यादव ने कानपुर के गंगाघाट से चुनाव अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर विशाल जनसभा के बीच जब श्री अखिलेश यादव विजय रथ पर सवार हुए तो उत्साही भीड़ ने गगनभेदी नारों से उनका स्वागत किया। नोटबंदी में पैदा हुए खजांची ने समाजवादी विजय रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री अखिलेश यादव ने रथ पर सवार होते समय सभी का अभिवादन किया और समाजवादी विजय रथ की सफलता और सहयोग के लिए धन्यवाद दिया।लाल टोपी लगाए कार्यकर्ताओं और नेताओं के समूह से गंगाघाट लालरंग से रंग गया और समाजवादी पार्टी के हरे, लाल रंग के लहराते झंडों से वातावरण में इंद्रधनुषी रंग बिखरते दिखाई पड़ रहे थे।

श्री अखिलेश यादव के अभूतपूर्व स्वागत में पूरा कानपुर उमड़ आया था। सड़क के दोनों किनारों पर बच्चे-बूढ़े, जवान और महिलाएं उनका अभिनंदन कर रहे थे। श्रमिक भी बड़ी संख्या में आए थे। उनके जिंदाबाद के नारों से माहौल गूंज रहा था। लोग यह बात कहते सुने गए कि जब-जब समाजवादी पार्टी की रथ यात्राएं निकली हैं प्रदेश की जनता ने विजय का आशीर्वाद दिया है। कार्यकर्ताओं में उत्साह हिलोरें मारने लगा। श्री अखिलेश यादव के समक्ष पूर्व सांसद श्री राजाराम पाल ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की।

श्री अखिलेश यादव ने कानपुर से विजय रथ यात्रा की शुरुआत के सम्बंध में कहा कि कानपुर औद्योगिक नगरी है। भाजपा राज में उद्योग बर्बाद हैं। जनता भाजपा के कुशासन, अन्याय, अत्याचार से पीड़ित है। भाजपा से उत्तर प्रदेश को धोखा मिला है। किसान अपमानित हुआ है। नौजवान की नौकरी, रोजगार छिन गया है, महंगाई बढ़ी है। इसलिए समाजवादी विजय रथ से जनता के बीच जा रहे हैं, जिससे उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा।

घाटमपुर में नेवेली लिग्नाइट बिजली घर के पास आयोजित जनसभा को सम्बोधित करते हुए श्री अखिलेश यादव ने कहा कि नेवेली लिग्नाहट बिजलीघर सपा सरकार में बनना शुरू हुआ। यदि इसे पूरा कर दिया गया होता तो यहां प्रदेश में बिजली सप्लाई बढ़ने के साथ देश के अन्य भागों को भी बिजली मिलती। भाजपा सरकार साढ़े चार

समाजवादी यात्राएं: बदलाव की वाहक

बुलेटिन ब्यूरो

यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि जब-जब श्री अखिलेश यादव चुनाव के पहले यात्राओं पर निकले हैं, प्रदेश की राजनीति में नए परिवर्तन की लहर आई है। इतिहास गवाह है कि जब-जब समाजवादी रथ चला है विजय पीछे-पीछे चली है और हर बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है।

साल में भी उसे पूरा नहीं कर पाई। सपा सरकार आने पर हम ही उद्घाटन करेंगे।

विजय यात्रा के दूसरे दिन 13 अक्टूबर को श्री अखिलेश यादव ने बुंदेलखंड के हमीरपुर स्थित कुरारा में मीडिया से वार्ता की और जनसभा को सम्बोधित किया। रास्ते में जगह-जगह उनका भव्य स्वागत हुआ। हमीरपुर डाक बंगले में उनसे बड़ी संख्या में समाजवादी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने मुलाकात की। विजय यात्रा को लेकर बुंदेलखंड के लोगों में भारी उत्साह दिखाई पड़ा। सड़कों के किनारे आम जनता, नौजवान, किसान-महिलाएं श्री अखिलेश यादव को देखने-सुनने के लिए इंतजार करते दिखे।

13 अक्टूबर को कालपी में एक बड़ी जनसभा का आयोजन महान दल द्वारा ठक्कर बाबा इन्टर कालेज मैदान में किया गया।

कालपी की इस सम्मान रैली को संबोधित करते हुए श्री अखिलेश यादव ने कहा कि महान दल के साथ कासगंज में जो संघर्ष शुरू किया वह कालपी तक दिखाई दे रहा है। महान दल के लोग भी किसान है और किसानों की समस्याओं से परिचित हैं। उन्होंने कहा कि सपा के साथ संघर्ष में बसपा-कांग्रेस के जो तमाम नेता शामिल हुए है उनका धन्यवाद। महान दल के अध्यक्ष श्री केशव देव मौर्य ने सपा को जिताने और भाजपा के सफाये का संकल्प जताया। 13 अक्टूबर की शाम कानपुर देहात के माती में हुई विशाल सभा को श्री अखिलेश यादव ने संबोधित किया। इस अवसर पर सपा की एक अन्य सहयोगी पार्टी जनवादी पार्टी (सोशलिस्ट) के अध्यक्ष डॉ. संजय सिंह चौहान अपने हजारों समर्थकों के साथ शामिल हुए।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव श्री राजेन्द्र चौधरी ने कहा है कि इस बार भी गरीबों, वंचितों, अल्पसंख्यकों, पिछड़ों और दलितों के बीच विश्वास जगाने में यह यात्रा निश्चय ही मील का पत्थर साबित होगी। कुशासन का अंत होगा।

उल्लेखनीय है कि 31 जुलाई 2001 से पहली क्रांति रथ यात्रा पर श्री अखिलेश यादव निकले थे। 12 सितम्बर 2011 को श्री अखिलेश यादव दूसरी समाजवादी क्रांति रथ यात्रा पर निकले थे। इन यात्राओं से प्रदेश की राजनीति में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए थे। जुल्मी सत्ताएं उखड़ गईं और राजनीति में शुचिता तथा पारदर्शिता को स्थान मिला।

श्री अखिलेश यादव के मुख्यमंत्रित्वकाल (2012 से 2017) में प्रदेश में विकास का रास्ता प्रशस्त हुआ। लोगों की जिंदगी में बदलाव आया। अब फिर जनता को विजय यात्रा की सफलता के साथ उम्मीद बंधी है कि प्रदेश में लोकतंत्र की बहाली होगी और उत्पीड़न तथा अत्याचार समाप्ति के साथ ही समाजवादी पार्टी की सरकार बहुमत के साथ 2022 में सत्ता में आएगी।

'यह यूपी के नव निर्माण की यात्रा

बुलेटिन ब्यूरो

विजय यात्रा के दौरान अपने संबोधनों में श्री अखिलेश यादव ने कहा कि यह यात्रा गंगा-जमुनी तहजीब को बचाने और उत्तर प्रदेश के नवनिर्माण के लिए है। उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाना है। यह तहजीब ही हमारी पहचान है। सभी धर्म के लोग प्रेम भाव से रहें, इस सोच को मजबूती देने के लिए यह यात्रा है। उन्होंने कहा गंगा से लेकर यमुना तक यह विजय रथ चलेगा। समाजवादी विजय रथ यात्रा किसानों, नौजवानों के हक और सम्मान के लिए निकली है।

उन्होंने कहा कि समाजवादी विजय रथ यात्रा भाजपा के सफाये तक चलती रहेगी। भाजपा राज में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। काला धन वापस नहीं आया, महंगाई थमी नहीं। पेट्रोल-डीजल-रसोई गैस और खाद, कीटनाशक के दाम आसमान चढ़ गए। किसान, गरीब, नौजवान सभी दुःखी है। यह सरकार गरीबों का हक छीन रही है। रोजी-रोजगार की उम्मीदें टूट गई हैं।

श्री यादव ने कहा कि समाजवादी सरकार बनने पर किसानों को बिजली मुफ्त में भी दे सकते हैं। सिंचाई मुफ्त होगी। जनता की सुविधा के लिए सपा सरकार ने एम्बुलेंस सेवा 108, 102 शुरू की थी। अपराधों पर नियंत्रण के लिए 100 व महिला सुरक्षा के लिए 1090 डायल सेवाएं शुरू की थी, इनका विस्तार होगा। उन्होंने कहा कि जनता में जो उत्साह दिख रहा है उससे लग रहा समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। दोबारा भाजपा सरकार नहीं आएगी। बाबा, बुल और बुलडोजर सभी जाएंगे। हम 400 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। उन्होंने कहा किसानों-नौजवानों, व्यापारियों, पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों की भी यह जीत होगी। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी काम करना चाहती है। यूपी को विकास के रास्ते पर ले जाना चाहती है।

श्री यादव ने सभी से भाजपा को हटाने का आव्हान करते हुए कहा कि भाजपा महंगाई बढ़ाकर मुनाफा कमा रही है। अपने समर्थक बड़े-बड़े लोगों को लाभ पहुंचा रही है। सबको पता है कि डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस के दाम बढ़ गए हैं लेकिन भाजपा को ही नहीं पता है। भाजपा अपने उद्योगपतियों के लाभ पहुंचाने के लिए काम कर रही है। उद्योग, कारखाने के लिए काम नहीं होगा तो रोजगार नहीं मिलेगा।

तस्वीरों में विजय यात्रा

समाजवादी
2022

समाजवादी पार्टी

समाजवादी पार्टी

समाजवादी पार्टी
बड़े का हाथ-युवा का साथ
विजय यात्रा
किसान, गरीब, महिला, युवा,
सबकी एक आवाज है हम

किसान, ग़रीब, महिला, युवा,
सबकी एक आवाज़ है
समाजवादी
विजय यात्रा
UP32G
N1990

फूलन देवी की मां बोलीं अखिलेश बनें सीएम!

बुलेटिन ब्यूरो

श्री अखिलेश यादव की यात्रा को दलित-वंचित-पिछड़े वर्ग से जबरदस्त समर्थन मिला। इसकी एक बानगी 13 अक्टूबर को यात्रा के तहत हो रही एक सभा के दौरान दिखी। जब सभा को संबोधित करते हुए श्री अखिलेश यादव की नजर भीड़ के बीच में खड़ी समाजवादी पार्टी की पूर्व सांसद स्वर्गीय फूलन देवी की मां मुला देवी पर पड़ी। वे फूलन देवी के गांव शेखपुर गुढ़ा के प्रधान रामबाबू निषाद के साथ सभा में आईं थीं। मुला देवी पर श्री अखिलेश यादव की नजर पड़ी तो वे फौरन उतरकर नीचे आए। मुला देवी भी अखिलेश की ओर बढ़ी और उनका माथा चूम लिया। जिससे माहौल भावुक हो गया।

भीड़ के बीच ही अखिलेश ने मुला देवी से उनके हालचाल पूछे। साथ ही सरकार बनने पर हर संभव मदद का वादा भी किया। मुला देवी ने अखिलेश से कहा, भगवान ऐसा बेटा सभी को दे। बाद में मुला देवी ने मीडिया को बताया कि उनकी अंतिम इच्छा यही है कि एक बार फिर से अखिलेश मुख्यमंत्री बनें।

श्री अखिलेश यादव ने यात्रा के दौरान अपने संबोधनों में दलितों-पिछड़ों के हक और सम्मान के लिए आवाज बुलंद की।

उन्होंने कहा कि भाजपा ने दलितों-पिछड़ों का हक और सम्मान छीना है। यह पिछड़ों का हक और सम्मान नहीं देना चाहती है। भाजपा पिछड़ों को गुमराह करती है। जातियों में लड़ाती है। इसीलिए हम समाजवादी लोग चाहते हैं कि पिछड़ी जातियों की गिनती हो जाए। सबको आबादी

जनता को भा रही अखिलेश की संवाद शैली

बुलेटिन ब्यूरो

श्री अखिलेश यादव में तमाम चुनौतियों को परास्त करने की ताकत है। भाजपा अपनी संकीर्ण मानसिकता के साथ ध्रुवीकरण की राजनीति चलाती है। लेकिन अखिलेश जी विकास की बात करते हैं। किसान, नौजवान, गरीब, महिलाओं और वंचितों की बात करते हैं। उनकी पीड़ा से अपने को जोड़ते हैं। महंगाई, रोजगार, आवास, शिक्षा-स्वास्थ्य जैसे सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दे उठाए। उन्होंने गरीब के दर्द पर मरहम भी लगाया। इससे जनसामान्य के बीच उनकी छवि अपने हमदर्द और मसीहा की बनी है। श्री यादव ने जनता से बेहतर संवाद की नई शैली विकसित की है।

श्री अखिलेश यादव ने बढ़ती महंगाई, ईंधन गैस की किल्लत जैसे मसलों को उभारा जिससे ज्यादातर महिलाओं को ही सामना करना पड़ता है। उन्होंने भीड़ में खड़े किसानों को भी सम्बोधित किया। उन्होंने यह बात बार-बार कहीं कि भाजपा ने किसानों को कुचलने और उनकी आवाज को दबाने का काम किया है। भाजपा का चरित्र ही किसान विरोधी हैं।

श्री यादव ने किसानों के दर्द को अपनी सभाओं में बार-बार उकेरा।कानून व्यवस्था के बिगड़ते हालात पर भी वे बोले। रोटी-रोजगार की मार झेल रहे नौजवानों के दर्द को भी उन्होंने साझा किया। श्री अखिलेश यादव की विशेषता यह है कि वे समाजवादी सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियों की चर्चा इस ढंग से करते हैं कि जनता को भाजपा की जनविरोधी नीतियों की स्वतः जानकारी होते देखी गई।

के अनुपात में हक और सम्मान मिल जाए। यहीं हमारा संविधान कहता है। यही बाबा साहब अम्बेडकर और डा. लोहिया कहते थे। श्री यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने जातीय जनगणना की मांग इसलिए उठाई है क्योंकि इससे सानुपातिक प्रतिनिधित्व की मांग पूरी होगी।

सामाजिक न्याय की अवधारणा को तभी साकार किया जा सकेगा। भाजपा ने नफरत फैलाने और आपस में एक दूसरे के बीच दूरी बढ़ाने का काम किया है।यह सरकारी संपत्तियों को बेचने वाली सरकार हैं। उन्होंने हवाई जहाज और एयरपोर्ट बेच दिए। सरकारी संस्थाएं बेच दीं।

अंग्रेजों ने एक कानून से कम्पनी को सरकार बना दी। भाजपा सरकारी चीजों को कम्पनियों के हाथों बेंच रही है। सब बिक जाएगा तो दलितों-पिछड़ों को आरक्षण कैसे मिलेगा।

निजीकरण बेशुमार आरक्षण पर वार

किसी जमाने में एक निजी अंग्रेजी कंपनी ने भारत में कारोबार करने के नाम पर देश पर ही अपना राज स्थापित कर लिया था। कंपनी की सरकार बन गई थी। मौजूदा भारत सरकार अपनी नीतियों के कारण फिर से देश को उसी रास्ते पर धकेल रही है। मोदी राज में अंधाधुंध रफ्तार से सरकारी कंपनियों का अस्तित्व समाप्त कर उन्हें निजी हाथों में सौंप देने के फैसले हो रहे हैं। जिस तेजी से सार्वजनिक उपक्रमों को खत्म किया जा रहा है उससे यह स्वाभाविक प्रश्न उठ रहा है कि जब सरकारी क्षेत्र बचेंगे ही नहीं तो सरकारी नौकरियों में संविधान प्रदत्त आरक्षण कैसे बचेगा? आरक्षण खत्म करने के भाजपा सरकार के इस छिपे हुए एजेंडे की पड़ताल कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार व लेखक ***दीपक मंडल:***

एयर इंडिया को टाटा ग्रुप को 18 हजार करोड़ रुपये में बेचने के फैसले पर मोदी सरकार और इसके समर्थक मुदित हैं। देश के गुलाबी अखबारों से लेकर चैनलों की चर्चाओं में तालियां पीटी जा रही हैं। कहा जा रहा है कि अमित शाह एंड पार्टी की सूझबूझ ने देश की गरीब जनता का डेढ़ लाख करोड़ रुपये का टैक्स बचा लिया, लेकिन बधाइयों, तालियों और वाहवाहियों के इस शोर में सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में लागू आरक्षण के ताबूत में ठोकी जा रही आखिरी कीलों की ठकठक भी तेज होती जा रही है। संविधान ने इन नौकरियों में दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों के लिए आरक्षण की जो व्यवस्था की है, उसे बड़ी ही सधी हुई रणनीति के जरिये बेअसर करने की साजिश तेज हो गई है।

पिछले लगभग पांच साल से सामाजिक न्याय की बुनियाद पर जिस कदर चोट हो रही है, उसने मौजूदा सरकार की मंशा साफ कर दी है। विनिवेश के बहाने पीएसयू (सार्वजनिक उपक्रमों) को निजी क्षेत्र के हाथों सौंपा जा रहा है। विश्वविद्यालयों में फैकल्टी की भर्तियां बहुत कम हो रही हैं और जो हो रही हैं, उनमें दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों की भागीदारी नदारद है।

सरकारी नौकरियों में जबरदस्त कटौती

यह संयोग नहीं है कि एयर इंडिया के निजीकरण को 'मुकाम' तक पहुंचाने से महज छह महीने पहले सिविल सर्विसेज के लिए निकाली गई वैकेंसी में दस फीसदी की कटौती कर दी गई। साल 2020 में इसके लिए 796 पद निकाले गए थे, लेकिन 2021 में इन पदों की संख्या घटा कर 712 कर दी गई। यह सिलसिला लगातार जारी है। देश में प्रशासनिक अफसरों की कमी के बावजूद सरकार यूपीएससी के जरिये इनकी भर्तियां लगातार घटा रही है। दूसरी ओर लेटरल एंट्री से अफसरों की भर्तियों पर जोर बढ़ता जा रहा है। यह सरकारी नौकरियों में दलितों, पिछड़ों और ओबीसी का आरक्षण खत्म करने की शुरुआत है और यह सब देश में बेहतर गवर्नेंस के नाम पर हो रहा हैष

सरकारी नौकरियों में आरक्षण पर चोट मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में शुरू हो गई थी, लेकिन दूसरे कार्यकाल में आरक्षण पर परोक्ष वार और तेज हो गए हैं। नीति-आयोग ने जो योजना तैयार की है, उसके मुताबिक सरकार 2021 से 2025 के बीच सार्वजनिक क्षेत्र की छह लाख करोड़ रुपये की संपत्ति निजी कंपनियों को बेच देगी। सरकार ने 34 पीएसयू की हिस्सेदारी निजी कंपनियों को बेचने की सहमति दे दी है. एलआईसी, आईडीबीआई, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, बीपीसीएल, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जैसी कंपनियों की लंबी फेहरिस्त है, जिन्हें विनिवेश के नाम निजी क्षेत्र को बेचा जा रहा है। सरकार का इस साल विनिवेश से 1.75 लाख करोड़ रुपये हासिल करने का लक्ष्य है।

पिछड़ों-दलितों की हैसियत घटाने की कोशिश

एक लोक कल्याणकारी राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की बड़ी भूमिका होती है। भारत जैसे आर्थिक और सामाजिक तौर पर बंटे हुए और भारी असमानता वाले देश में गरीबी दूर करने और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने में इनकी बड़ी भूमिका रही है। भारतीय समाज की विडंबना यह है कि दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का राजनीतिक सशक्तिकरण तो हो रहा है लेकिन आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण से वे दूर हैं।

एससी-एसटी समुदायों के लिए संविधान बनने के साथ ही सार्वजनिक उपक्रमों, सरकारी विभागों और विश्वविद्यालयों की नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था शुरू हो गई थी। इसका उन्हें लाभ भी मिला। वहीं नब्बे के दशक में मंडल आयोग की रिपोर्ट के बाद पिछड़ों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था हुई। इसने इस समुदाय का सशक्तिकरण किया और ये राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक तौर पर और मुखर हुए। लेकिन सत्ता प्रतिष्ठानों में बैठे वर्चस्ववादी तबके को यह रास नहीं आ रहा है। लिहाजा सरकारी नौकरियों में आरक्षण को खत्म करने के लिए विनिवेश जैसे हथकंडे का सहारा लिया जा रहा है. क्योंकि उन्हें मालूम है कि यह पिछड़ों की

फोटो स्रोत: गूगल

आर्थिक और सामाजिक हैसियत कम करेगा और अंततः उनकी राजनीतिक ताकत भी कमजोर हो जाएगी।

1980 के दशक में प्रशासनिक सेवाओं, सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और सार्वजनिक उपक्रमों की नौकरियों में एससी-एसटी और पिछड़ों के प्रतिनिधित्व से जुड़े आंकड़ों पर गौर करें-

1984 में केंद्रीय प्रशासनिक सेवाओं के ग्रुप सी नौकरियों में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व 14 फीसदी था, जबकि उनकी आबादी 16 फीसदी के करीब है। 2003 में ग्रुप बी की नौकरियों में उनकी हिस्सेदारी 13.3 फीसदी थी। 2015 में ग्रुप ए की नौकरियों में अनुसूचित जातियों के लोगों का प्रतिनिधित्व 13.3 फीसदी था। 2004 में केंद्र सरकार की सार्वजनिक कंपनियों (CPSE) में उनका प्रतिनिधित्व 14.6 फीसदी था जो 2014 में बढ़ कर 18.1 फीसदी हो गया। जबकि इस बीच उनकी साक्षरता दर में भारी इजाफा हुआ था। 1981 में अनुसूचित जातियों की साक्षरता दर 21.38 फीसदी थी वहीं 2011 में यह बढ़ कर 66.1 फीसदी हो गई।

मंडल कमीशन की सिफारिशों की बदौलत सरकारी नौकरियों में पिछड़ों को आरक्षण की व्यवस्था के बाद पिछड़ी जातियों का प्रतिनिधित्व इनमें तेजी से बढ़ा। देश की आबादी में पिछड़ी जातियों की हिस्सेदारी तकरीबन 52 फीसदी है।

2013 में केंद्र सरकार की क्लास 'ए' की नौकरियों में इन जातियों का प्रतिनिधित्व 8.37 फीसदी था. क्लास 'बी' की नौकरियों में उनका प्रतिनिधित्व 10.1 फीसदी और क्लास 'सी' की नौकरियों में 17.98 फीसदी था। 2004 में केंद्र सरकार की सार्वजनिक कंपनियों की नौकरियों में इन जातियों का प्रतिनिधित्व 16.6 फीसदी था जो 2014 में बढ़ कर 28.5 फीसदी हो गया।

साफ है कि सरकारी विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों की नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था से सामाजिक और आर्थिक न्याय से वंचित रहे समुदाय मजबूत हुए हैं। इन सेक्टरों में इनकी बढ़ती भागीदारी ने इन्हें राजनीतिक रूप से भी ज्यादा मुखर बनाया. लेकिन यह सशक्तिकरण मोदी सरकार को रास नहीं आ रहा है।

सिविल सर्विसेज, रेलवे से लेकर बैंकों तक में घटी नौकरियां

यूपीए सरकार के तहत साल 2006 से 2014 के बीच निजी क्षेत्र में नौकरियां 5.5 लाख से बढ़ कर 7.5 लाख तक पहुंच गईं लेकिन इसके बाद यह आंकड़ा गिरता ही जा रहा है। मिसाल के तौर पर यूपीएससी के जरिये भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में भर्तियों की संख्या घटा दी गई हैं। 2014 में केंद्र सरकार की प्रशासनिक सेवाओं के लिए 1236 भर्तियां निकाली गईं लेकिन 2018 तक आते-आते इनकी संख्या घट कर 759 हो गई। 2021 में इन पदों की संख्या और घटा कर 712 कर दी गई।

इसी तरह केंद्र सरकार के कर्मचारियों की संख्या में भी भारी गिरावट देखने को मिल रही है। इस वजह से सार्वजनिक कंपनियों में दलित कर्मचारियों की संख्या 16 फीसदी घट गई है। यह संख्या 5.40 लाख से घट कर 4.55 लाख पर पहुंच गई है। इन कंपनियों में भले इनकी भागीदारी बढ़ी हो लेकिन नौकरियों की संख्या घटती गई है। 2008 में ओबीसी रिजर्वेशन का लाभ लेने वालों की संख्या 14.89 लाख थी लेकिन 2012 तक यह बढ़ कर 23.55 लाख हो गई, लेकिन इसी साल इनकी संख्या घट कर 23.38 लाख पर आ गई।

इसके बाद हालात और बदतर हो गए। 2014 में भाजपा ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में कहा था कि वह प्रशासनिक सेवाओं में लैटरल एंट्री से 'विशेषज्ञों' लाएगी। जाहिर है इसमें आरक्षण लागू नहीं होना था। 2019 में ऐसे 'विशेषज्ञों' की भर्ती के लिए 6000 कैंडिडेट्स के इंटरव्यू लेकर 89 लोगों को चुना गया। इनमें से दस की भर्तियां होनी थीं। उसी साल सरकार ने लोकसभा में बताया कि 2016-17 में यूपीएससी की परीक्षाओं के जरिये 6103 कैंडिडेट्स की भर्तियां हुईं लेकिन 2019-20 तक आते-आते यह संख्या 30 फीसदी घट कर 4,399 रह गई।

जैसे-जैसे सरकारी कंपनियों का निजीकरण तेज होगा, उनमें आरक्षण नीति भी उसी गति से गायब होती जाएगी। जाहिर है यह देश के सत्तर फीसदी पिछड़े, दलित और आदिवासियों को और हाशिये पर धकेल देगी

2016-17 में स्टाफ सेलेक्शन कमीशन ने 68,880 कैंडिडेट्स की भर्तियां की थीं लेकिन 2020-21 में यह 96 फीसदी घट कर सिर्फ 2,106 रह गई।

रेलवे इस देश मे सबसे ज्यादा नौकरियां देने वाला विभाग है। 2106-17 में रेलवे में 27,427 कैंडिडेट्स की भर्तियां हुई थीं लेकिन 2020-21 में यह संख्या घट कर सिर्फ 3,873 रह गई। सार्वजनिक बैंकों के लिए कर्मचारियों की भर्ती करने वाला इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन (IBPS) ने 2019 में प्रोबेशनरी अफसरों के 4,336 पदों पर बहाली के लिए विज्ञापन निकाला था लेकिन 2020 में इनकी संख्या घट कर सिर्फ 1,167 रह गई।

विनिवेश के बहाने आरक्षण पर चोट

विनिवेश के जरिये सार्वजनिक कंपनियों की हिस्सेदारी बेचने वाली विनिवेश प्रकिया से जुड़े सरकार के आला अफसरों ने साफ कहा है कि निजी कंपनियों पर आरक्षण के लिए जोर नहीं दिया जाएगा। बीपीसीएल की हिस्सेदारी बेचने के मामले में सरकार ने अपना नजरिया साफ कर दिया है।

23 मार्च 2021 को संसद में तत्कालीन भारी उद्योग और सार्वजनिक उपक्रम मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के हवाले साफ कहा था कि आरक्षण नीति सिर्फ सरकारी कंपनियों में ही लागू है। बीपीसीएल में विनिवेश के बाद यह सरकारी कंपनी नहीं रह जाएगी इसलिए इसकी नौकरियों में पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों के आरक्षण की नीति खुद-ब-खुद खत्म हो जाएगी।

साफ है कि जैसे-जैसे सरकारी कंपनियों का निजीकरण तेज होगा, उनमें आरक्षण नीति भी उसी गति से गायब होती जाएगी। जाहिर है यह देश के सत्तर फीसदी पिछड़े, दलित और आदिवासियों को और हाशिये पर धकेल देगी। इन सार्वजनिक उपक्रमों ने इस बहुजन आबादी के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण में जो अहम भूमिका निभाई थी, वो अब बीते दिनों की बात हो जाएगी। न जाने आगे कब तक देश की आबादी का यह सबसे बड़ा हिस्सा मौजूदा सरकार के इस गुनाह का सलीब ढोता रहेगा!

(यह लेखक के अपने विचार हैं)

देश को गुलाम बनाएगी मोदी की मुद्रीकरण योजना

लगातार तीन साल से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जब लाल किले के अपने भाषण में एक लाख करोड़ के निवेश से देश के 'इंफ्रास्ट्रक्चर' को दुरुस्त करने की घोषणा करते जा रहे थे तब उनके अब तक के कामकाज के इतिहास-भूगोल-नागरिक शास्त्र के साथ-साथ उनके स्वभाव और कार्यशैली से परिचित लोगों के मन में खतरे की घंटी बजने लगी थी।

पिछले साल तो कोरोना का शोर था तो नीति आयोग और वित्त मंत्रालय ने चुप्पी साध ली थी लेकिन इस बार मोदी जी के भाषण के कुछ समय बाद ही, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 7 सितंबर को ' नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्रोजेक्ट'(एनएमपीपी) की घोषणा की तब साफ हुआ कि मोदी सरकार ने देश की सम्पदा को बेच खाने की कितनी व्यापक और षड्यंत्रकारी योजना तैयार कर रखी है। नीति आयोग का इससे संबंधित दस्तावेज दो खंडों का है और इसे पलट कर देखने भर से डर लगता है कि पूरी तरह लागू होने के बाद देश में अपना अर्थात सरकारी और सार्वजनिक क्या बचेगा और हमें सड़क से लेकर मकान और भोजन की सार्वजनिक योजनाओं के लिए क्या-क्या कुछ चुकाना

अरविन्द मोहन
लेखक, वरिष्ठ पत्रकार

होगा? अगर हर मद का खर्च हमें ही करना होगा तो फिर सरकार के रहने का और हमसे टैक्स लेने का क्या मतलब है? हर चीज पर जीएसटी वसूलने का क्या मतलब है?

अभी घोषित योजना के अनुसार सरकार अगले चार सालों में इस 'पीपी' योजना से करीब छह लाख करोड़ रुपए बाजार से उठाएगी और उसके बदले निजी कंपनियों और उद्यमियों को राजमार्ग, रेल, इंजन, हवाई जहाज, हवाई अड्डे, बन्दरगाह, जमीन के अन्दर बिछी टेलिकम्युनिकेशन की फाइबर लाइनें, पेट्रोलियम को एक से दूसरी जगह ले जाने के लिए बिछी पाइपलाइनें, बिजलीघर, बिजली ट्रांसमिशन की लाइनें, प्राकृतिक गैस की खदान और पाइपलाइनें, कोयला और अन्य खनिजों की खदानें, खनन, आवास एवं शहरी विकास की सार्वजनिक परिसंपत्तियों, परिवहन की व्यवस्था और खाद्य और आपूर्ति की परियोजनाओं समेत कई अन्य क्षेत्रों में भी निजी क्षेत्र को मिल्कियत में हिस्सा देने के साथ राजस्व उगाहने का अधिकार और नए निवेश का अवसर देगी।

इस साल इन 'पीपी' योजना से 89190 करोड़, अगले साल 162422 करोड़, उससे अगले साल 179544 करोड़ और उससे अगले साल 167345 करोड़ रुपए हासिल करेगी। सरकार का दावा है कि यह धनराशि इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में खर्च होगी (लेकिन यह साफ नहीं है कि जब सब कुछ निजी हाथों में ही दे दिया जाएगा तब यह निवेश कहां होगा)।

सरकार का यह भी कहना है कि इस योजना में मिल्कियत नहीं बिकेगी, राइट्स अर्थात उस सम्पत्ति के उपयोग, संचालन और राजस्व वसूलने का अधिकार 'भर' मिलेगा और तय समय बाद संपत्ति सरकार के पास वापस लौट आएगी। यह योजना 'स्ट्रक्चर्ड पार्टनरशिप' वाली होगी और इससे अभी पैसा मिलने के साथ-साथ नियमित राजस्व मिलेगा और नया निजी निवेश भी आएगा।

जैसा पहले कहा गया है, कोरोना काल का लाभ लेकर नीति आयोग ने बहुत ही व्यवस्थित योजना बनाई है और इस षड़यंत्र को तोड़ना मुश्किल है और समय बीतते जाने के साथ और मुश्किल होता जाएगा। यह मामला सूदखोर महाजन के पास मनमानी शर्तों पर जमीन या जायदाद बंधक रखने, उस सम्पदा से बाजार में कमाई करते रहने, उसमें मनमाना निवेश करके या बाजार की जरूरतों के अनुरूप बदलाव करके अपने हिसाब से बनाने-चलाने की छूट लेने वाला है।

एक बार पूंजी लगाने, नई तकनीक/मशीनें लाने और प्रबंधन हाथ में लेने के बाद कौन ऐसा उद्यमी होगा जो हाथ आई दुधारू गाय को वापस जाने देगा! अभी की योजना से सड़क, रेल, दूरसंचार, विमानन जैसे पांच क्षेत्रों से ही 83 फीसदी पैसा आने की उम्मीद की जा रही है

जिस तरह गरीब आदमी अक्सर बन्धक पड़ी अपनी सम्पत्ति के लिए महाजन को सूद चुकाते-चुकाते मर जाता है और उस संपत्ति से भी हाथ धो बैठता है, कुछ वैसा ही खेल यह भी होने जा रहा है।

एक बार पूंजी लगाने, नई तकनीक/मशीनें लाने और प्रबंधन हाथ में लेने के बाद कौन ऐसा उद्यमी होगा जो हाथ आई दुधारू गाय को वापस जाने देगा! अभी की योजना से सड़क, रेल, दूरसंचार, विमानन जैसे पांच क्षेत्रों से ही 83 फीसदी पैसा आने की उम्मीद की जा रही है।

हम चमचमाती सड़कों पर चलने का 'मोल' जान गए हैं। हर सौ-पचास मील की दूरी पर 'पीपीपी' कंपनी के मुस्टंडे टोल-टैक्स के नाम पर वसूली करते हैं। निजी बिजली वितरण कंपनियों का अनुभव भी सबको हुआ है और दूरसंचार क्षेत्र या विमानन का काम तो पूरी तरह निजी हाथों में जाने का अनुभव भी हम सबने भुगता है।

जब आपके लिए यात्रा करना बेहद जरूरी हो तो विमान का टिकट बड़े मजे से पांच-छह गुना तक महंगे हो जाते हैं और सरकार कुछ नहीं करती। अब तो ऐसा ही लोकल टैक्सी ही नहीं बल्कि बिना एक आदमी का खाना बनाए अरबों का भोजन व्यवसाय हथियाने वाली कंपनियां भी करने लगी हैं।

डाक-तार की जगह आई कूरियर कंपनियां देश के बेरोजगार नौजवानों को किन शर्तों और तनख्वाह पर काम कराती हैं यह सब जानते हैं। फोन का कुल कारोबार तो पहले ही निजी हाथों में जा चुका है। अब बचा-खुचा नेटवर्क, जमीन में पड़े फाइबर केबल के नेटवर्क और टावरों को निजी हाथों में (वह भी पूरा पैसा न लेकर एक अंश ही राशि में) देने की योजना आ गई है।

कुल 26700 किमी राजमार्ग, कई सौ स्टेशनों, कई खंडों के रेल मार्ग, रेलवे के

इंजन-डिब्बे, बिजली लाने ले जाने के 28608 सीकेटी किमी लाइन, 2.86 लाख किमी ऑप्टिकल फाइबर लाइन, 14917 कम्युनिकेशन टावर, 8154 किमी गैस पाइपलाइन, 15 स्टेशन, 15 नए एअरपोर्ट, मौजूदा एअरपोर्टों के अलग-अलग पचासों कामों का जिम्मा, 160 कोयला खदान, नौ बन्दरगाहों पर 31 प्रोजेक्ट, 21 करोड़ टन के गोदाम, दो नेशनल स्टेडियम, दो बिजनेस सेंटर, अनेक पुरानी सरकारी कालोनियां, आईटीडीसी के होटल, गेस्ट हाउस जैसी सरकारी आवासीय व्यवस्थाओं जैसी न जाने कितनी ही चीजों को इस 'पीपी' योजना को पिला देना है!

एक तो जिस सरकार ने ऐसे कामों में शायद ही गिनवाने लायक कोई चीज खड़ी की है या पर्याप्त पूंजी लगाई है, उसे इन सब चीजों को निजी हाथों में सौंपने और लाखों करोड़ रुपए उठाकर कहीं सेंट्रल विस्टा बनवाने तो कभी सैकड़ों करोड़ रुपए का विमान प्रधानमंत्री के लिए खरीदने का क्या हक है?

बल्कि इस सूची को देखने के बाद दिमाग इसी बात पर दौड़ता है कि अब सरकार की नजर से कौन सी चीज बच गई है जिसे वह नहीं बेचना या अपने प्रिय उद्यमियों को नहीं सौंपना चाहती।

जब यह लेख लिखा जा रहा है देश के एकमात्र बची सरकारी विमानन कम्पनी को बेचा जा रहा है और बिजलीघरों में कोयले की कमी (जिसकी अभी कोई तात्कालिक वजह न समझ आती है न बताई गई है) का बहाना बनाकर कम्पनियों के 'कैप्टिव माइंस' से कोयला बेचने की इजाजत देने का फैसला लिया जा रहा है. यह कांग्रेसी राज के कोल-गेट घोटाले का मोदी संस्करण है.

पर इन चिंताओं से भी बड़ी चिंताएं हैं और इन सवालों से भी बड़े सवाल अनुत्तरित हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि अगर मोदी जी की योजना 111 लाख करोड़ रुपए की है तो इस 'तुच्छ' छह लाख करोड़ रुपए के लिए इतनी सारी सार्वजनिक संपत्तियों को निजी हाथ में क्यों सौंपा जा रहा है। जहां से वह धन

फोटो स्रोत: गूगल

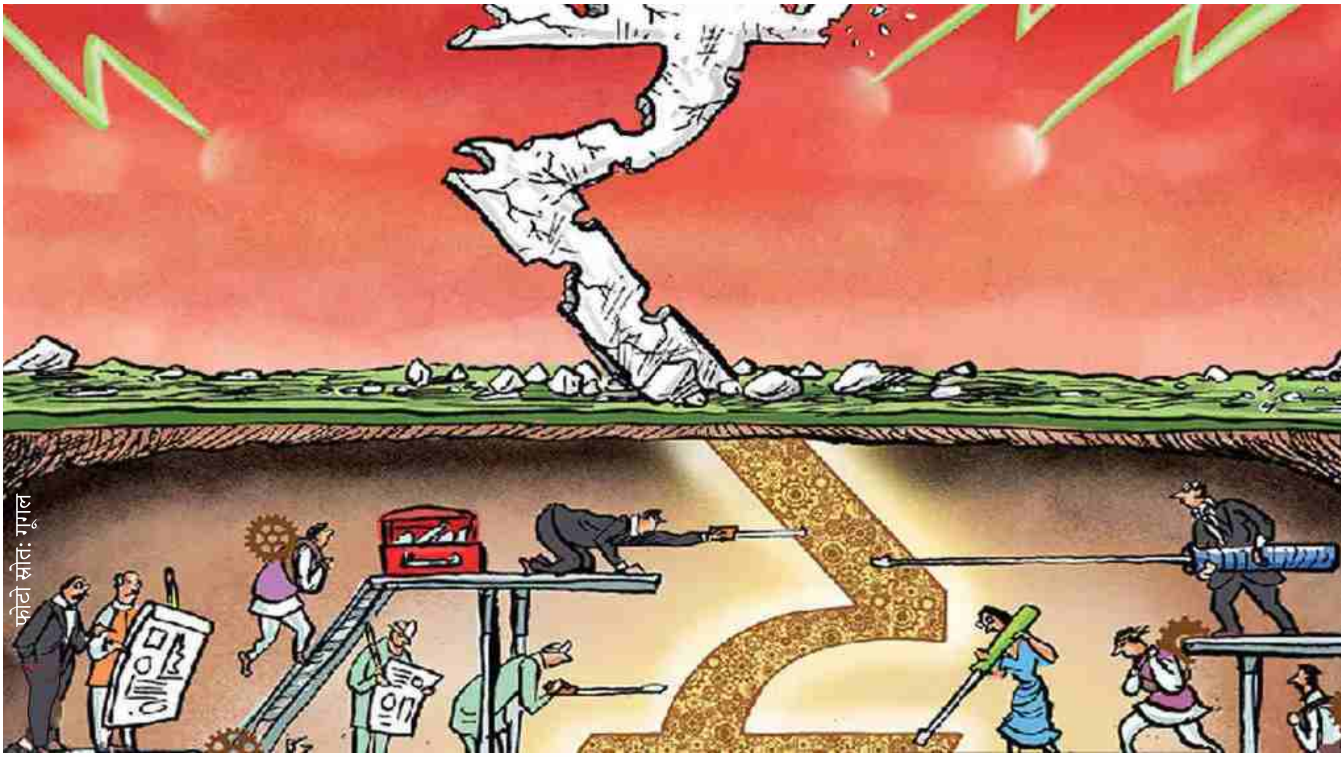

फोटो स्रोत: गूगल

आएगा वहीं से इतनी रकम और का इंतजाम क्यों नहीं कर लिया जाता। फिर जब विनिवेशीकरण और सरकारी कंपनियों को सीधे बेचने का काम चल ही रहा है (अभी भी भारत अर्थ मूवर्स समेत पांच कंपनियों को बेचने की प्रक्रिया जारी है) तब इन मोनेटाइजेशन अर्थात मुद्रीकरण के नाम से बहुत कम ही राशि लेकर निजी कंपनियों के हवाले सारा बना बनाया ढांचा क्यों सौंपा जा रहा है? कहीं अडानी, अम्बानी, टाटा और बिड़ला समूह जैसे जमे जमाए लोगों को सब कुछ सौंपने की तैयारी तो नहीं है।

दूरसंचार तो अम्बानी के हवाले जाता लगता है तो वहीं बंदरगाह, हवाई अड्डा और कृषि से जुड़े भंडारण और विपणन के कारोबार अडानी को, और अगर सरकार इस मुल्क के सारे संसाधनों का गार्जियन होकर कर लगाने, बांड जारी करने से लेकर नोट जारी करने तक का अधिकार रखकर इतनी पूंजी नहीं जुटा सकती तो निजी कंपनियां और उद्यमी कहां से धन ले आएंगे?

फिर इस व्यवस्था में विवाद निपटारे का मसला भी उसी तरह गोल-मोल रखा गया है जैसा कृषि कानूनों में है। जब ताकतवर से खतरा हो तब कानूनी पारदर्शिता जरूरी है क्योंकि महाजन और कर्ज लेने वाले की सारी कहानियां और अनुभव महाजन के ही जीतने का है।

जो बात इससे भी बड़ी है वह यह कि जब आपकी और आपके मुल्क की 'औकात' नहीं है तो ऐसे हवाई किले बनाने की क्या जरूरत है, और हमने मोदी मार्का काफी सारे हवाई किले देख लिए हैं। हर नागरिक को काले धन की वापसी से 14-15 लाख रुपए मिलने, सालाना दो करोड़ रोजगार, हर साल एक करोड़ लोगों को आवास, एक फैसले से सारे काले धन की समाप्ति, आतंकवाद की कमर टूटने, किसानों को लागत का दोगुना दाम देने और मोदी जी द्वारा ट्रम्प की जीत सुनिश्चित करने से लेकर न जाने क्या क्या!

उनका अभी तक एक ही फलितार्थ दिखता है- सारी असफलताओं के बावजूद नरेन्द्र मोदी का गद्दी पर विराजमान होना, लेकिन अब जो नया सपना भाई साहब तीन साल से लाल किले से बताते रहे हैं उससे तो देश ही बिक जाएगा, नई गुलामी आ जाएगी, शिक्षा और स्वास्थ्य का खर्च तो कुछ ही लोग उठा पाएंगे, सड़क पर चलने, रेल पर चढ़ने, फोन करने, गैस-पेट्रोल का उपयोग करने, बिजली जलाने में भी सभी लोग सक्षम नहीं होंगे।

जिनके पास पैसा है उनके लिए सब कुछ होगा, बाकी सबके लिए जै श्रीराम. यह तो घर की पुरानी चांद बेचकर राशन लाने जैसा भी नहीं है. इसमें तो कुछ बचेगा ही नहीं!

(यह लेखक के अपने विचार हैं)

सेल !
LIC
भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA
Bharat Petroleum
सार्वजनिक क्षेत्र

मोदी राज में विनिवेश

यानी देश की संपत्ति बेच डालो!

प्रेम कुमार
वरिष्ठ पत्रकार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारा दिया है- 'मोनेटाइज एंड मॉर्डनाइज'। इसका अर्थ है कि जो संपत्तियां देश के पास हैं और निष्क्रिय हैं उन्हें बेचकर या लीज पर देकर या ऐसे ही उपायों से रकम पैदा की जाए। फिर उस रकम से देश को आधुनिक बनाया जाए। इसका दूसरा मगर छिपा अर्थ यह है कि अगर मोनेटाइज नहीं होगा तो देश मॉडर्नाइज नहीं होगा।

आधुनिक भारत के निर्माता कहे गये पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कभी मॉडर्नाइज के लिए मोनेटाइजेशन को जरूरी नहीं समझा। वे भी तब रेलवे की संपत्ति बेच सकते थे जिसका ढांचा अंग्रेजों ने खड़ा किया था। इसके बजाए इस्पात, तेलसंशोधन, बिजली संयंत्र, कोयला के उपयोग, परमाणु अनुसंधान जैसे क्षेत्रों पर पंडित नेहरू ने काम किए और देश को एक से बढ़कर एक महारत्न, नवरत्न कंपनियां दीं।

अब 21वीं सदी में मोदी सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की इन बेशकीमती कंपनियों को बेचकर ही भारत को मॉडर्नाइज करने का सपना दिखा रही है। प्रश्न यह है कि इन कंपनियों के विनिवेश या इनके निजीकरण से देश आधुनिक होगा या फिर स्वातंत्र्योत्तर आधुनिक भारत का स्वरूप और विकृत हो

जाएगा?

घाटे वाली कंपनियां बढ़ीं लेकिन लोक उपक्रमों से मुनाफा नहीं घटा

भारत में महारत्न, नवरत्न और अन्य रत्नों को जोड़ लें तो 250 सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं। 90 के दशक में उदारीकरण की शुरुआत के बाद के पहले 15 सालों में यह प्रवृत्ति देखी गयी कि लाभ कमाने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की संख्या घटती गयी और घाटे में रहने वाली ऐसी कंपनियों की संख्या बढ़ती चली गयी। फिर भी कुल मिलाकर मुनाफा घटा नहीं, बल्कि बढ़ा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बंद होने के डर से अच्छी सेहत वाली कंपनियों ने खुद में सुधार किया।

विनिवेश का आरंभिक मकसद जनता की गाढ़ी कमाई को सफेद हाथी बनते जा रहे सार्वजनिक उपक्रम पर बर्बाद होने से रोकना था। मगर, इसका मकसद यह कतई नहीं था कि देश को सार्वजनिक उपक्रम की कंपनियों से छुटकारा दिलाया जाए या फिर उन्हें निजीकरण के नाम पर औने-पौने दाम पर बेच दिया जाए।

विनिवेश की प्रक्रिया नियंत्रित और धीमी रही तो इसकी सबसे बड़ी वजह थी कि विनिवेश को तब आमदनी के स्रोत के तौर पर नहीं देखा गया। 1991-92 से 2000-01 के बीच यानी शुरुआती 10 साल में विनिवेश से 54,300 करोड़ की रकम हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था लेकिन 20,078.62 करोड़ रुपये ही जुटाए जा सके।

वाजपेयी सरकार को विनिवेश का अंजाम भुगतना पड़ा

सितंबर 2001 में जब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने विनिवेश मंत्रालय का गठन किया तो उसके बाद से विनिवेश की प्रक्रिया ने तेजी पकड़ी। अंजाम यह हुआ कि 2004 में वाजपेयी सरकार लौटकर नहीं आ सकी। मगर 2001 से 2004 के बीच 38,500 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले 21,163.68 करोड़ रुपये विनिवेश से जुटाए गये।

विनिवेश का आरंभिक मकसद जनता की गाढ़ी कमाई को सफेद हाथी बनते जा रहे सार्वजनिक उपक्रम पर बर्बाद होने से रोकना था। यह नहीं कि सार्वजनिक उपक्रम की कंपनियों को निजीकरण के नाम पर औने-पौने दाम पर बेच दिया जाए

2004 से 2009 के बीच यूपीए-1 में विनिवेश की गति बिल्कुल धीमी रही। ऐसा संभवत: इसलिए हुआ क्योंकि नयी सरकार अटल सरकार की तरह विनिवेश का खामिजाया भुगतने की स्थिति पैदा करना नहीं चाहती थी। महज 8,515.93 करोड़ रुपये ही विनिवेश से जुटाए जा सके। लेकिन, यूपीए 2 में विनिवेश की रफ्तार बढ़ी। फिर भी विनिवेश से जुटाई गयी रकम लक्ष्य का करीब 60 फीसदी ही रही। हालांकि यूपीए 2 को भी विनिवेश की गति बढ़ाने का खामियाजा भुगतना पड़ा।

मोदी सरकार में निजीकरण में बदल गयी विनिवेश प्रक्रिया

2014 में जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी तो विनिवेश से धन जुटाने के मकसद में भी मानो पंख लग गये। पहले ही वर्ष में मोदी सरकार ने लक्ष्य का 75 फीसदी विनिवेश संभव कर दिखलाया। अगले वर्ष लक्ष्य से ज्यादा विनिवेश से रकम जुटा ली गयी। 2017-18 मे लक्ष्य के दुगुने से भी बड़ी रकम विनिवेश के जरिए जुटायी गयी। कोरोना प्रभावित वर्ष 2019-20 में भी 61 फीसदी विनिवेश का लक्ष्य पूरा हुआ।

2021-22 में विनिवेश का लक्ष्य 2.1 लाख करोड़ रखकर मोदी सरकार ने विनिवेश के मायने ही बदल दिए। अब विनिवेश का मतलब सार्वजनिक कंपनियों को बेचकर रकम जुटाना हो गया ताकि बजट के दबाव को कम किया जा सके या फिर राजस्व घाटे को पाटा जा सके।

मोदी सरकार ने अब खुलकर कहना शुरू कर दिया है- “Government has no business to be in Business.” थोड़ा स्पष्ट करें तो मोदी सरकार कह रही है कि सरकार का काम बिजनेस करना नहीं है। मगर, सरकार का काम चलते हुए बिजनेस को खत्म करना भी नहीं होता। विनिवेश का मतलब ऐसा कभी नहीं था कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का अस्तित्व ही मिटा डाला जाए।

1990 के पहले लगभग 40 साल तक

फोटो स्रोत: गूगल

सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों को खड़ा करने और उसका नफा-नुकसान समझने-बूझने में लगाया। मगर, 1990 के बाद से पिछले 30 साल में लगातार विनिवेश प्रक्रिया के माध्यम से सार्वजनिक उपक्रमों का मनोबल गिराने का काम किया गया है। इसके बावजूद मुनाफे में रहने वाली या घाटे में रहने वाली कंपनियों की संख्या में कोई बड़ा फर्क नहीं आया। पिछले पांच साल में दो तिहाई सार्वजनिक कंपनियां लगातार मुनाफे में रही हैं, जबकि एक तिहाई घाटे में। 2012-13 में भी यही स्थिति थी जब 150 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम फायदे में थे और 80 ऐसे उपक्रम नुकसान में थे।

लाभ में हो या घाटे में, सार्वजनिक कंपनी बिकेगी

लोकसभा में दी गयी जानकारी यह बताती है कि सार्वजनिक क्षेत्र की 30 कंपनियां लगातार नुकसान में रही हैं। अगर सरकार ऐसी कंपनियों का निजीकरण करने की पहल करती तो उसका मकसद घाटे से पीछा छुड़ाना माना जाता। मगर, अब मोदी सरकार ने विनिवेश नीति को लाभ-हानि से बिल्कुल अलग कर दिया है। विनिवेश का मतलब निजीकरण और निजीकरण का मतलब सरकारी कंपनियों के अस्तित्व को मिटा डालना हो गया है। सार्वजनिक सेक्टर से जुड़ी यही नयी नीति है।

मोदी सरकार ने करीब सौ संपत्तियों को बेचकर 2.5 लाख करोड़ रुपए जुटाने का इरादा सामने रखा है। अगले 4 साल में 6 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य लेकर सरकार चल रही है।

डिपार्टमेंट ऑफ इंवेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट के मुताबिक 2021-22 के वित्तीय वर्ष में कुल प्राप्ति 13,686.6 करोड़ है। इनमें विनिवेश से प्राप्ति 9110.56 करोड़ है जबकि लाभांश के रूप में प्राप्ति 4,576.04 करोड़ रुपये है। स्पष्ट है कि विनिवेश को लेकर जितनी महत्वाकांक्षी सरकार है हकीकत में ये आंकड़े उससे कोसों दूर हैं। अगर सरकार अपने घोषित मकसद में सफल होती है तो सार्वजनिक कंपनियों का अस्तित्व मिट जाएगा।

विनिवेश की प्रक्रिया में ताजा नाम एअर इंडिया का जुड़ गया है जिससे सरकार को 18 हजार करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई है। एक साल की देरी से यह प्रक्रिया पूरी हुई है। अगला नंबर एलआईसी का है। सरकार 2021-22 के अंतिम तिमाही तक एलआईसी के विनिवेश प्रक्रिया को अंजाम दे सकती है।

एक अनुमान के मुताबिक 2021-22 में सरकार का खर्च 35.7 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है। प्राप्ति का अनुमान 24.1 लाख करोड़ है। राजस्व घाटा 11.17 लाख करोड़ यानी जीडीपी का 5.2 फीसदी तक हो सकता है। विनिवेश से अधिक से अधिक रकम जुटाने की कवायद की जा रही है। खर्च चलाने के लिए अतीत में जमा की गयी संपत्ति को बेचा जा रहा है। इस रकम का इस्तेमाल जनकल्याणकारी योजनाओं में नहीं हो रहा है। ऐसे में धन के बेहतर इस्तेमाल का जो तर्क प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते रहे हैं, वह जमीन पर दिखाई नहीं देता।

(यह लेखक के अपने विचार हैं)

लोकतंत्र के लिए जरूरी है जाति जनगणना

फोटो स्रोत: गूगल

अरुण कुमार त्रिपाठी
वरिष्ठ पत्रकार

भारतीय लोकतंत्र की हत्या और उसकी तानाशाही की ओर चल रही यात्रा पर आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से 24 जून 2021 को एक पुस्तक प्रकाशित हुई है। पुस्तक का नाम है ` टू किल ए डेमोक्रेसीः इंडियाज पैसेज टू डेस्पाटिज्म'(To Kill a Democracy: India's Passage to Despotism)। इसके लेखक हैं देबाशीष राय चौधरी और जान कीने।

उनका कहना है कि भारत में लोकतंत्र की हत्या के लिए `सामाजिक मृत्यु' जिम्मेदार है। यह `सामाजिक मृत्यु' तब होती है जब समाज में सामाजिक और आर्थिक स्तर पर भारी असमानता होती है। व्यक्ति की गरिमा का ध्यान नहीं रखा जाता। स्वास्थ्य प्रणाली का ध्वस्त होना, लंबे समय से चली आ रही भुखमरी, जमीनों पर कब्जा करने की प्रवृत्ति, पानी और हवा का प्रदूषण, धार्मिक संकीर्णता, व्यापक निरक्षरता, कर्ज का

जाल, बाल दासता, जाति, लिंग और धर्म संबंधी हिंसा इन सबने मिलकर सामाजिक लोकतंत्र की संभावना को नष्ट कर दिया है। यही वजह है कि भारत में लोकतंत्र की हत्या हो रही है और हम तानाशाही की ओर बढ़ रहे हैं।

गंभीर रूप से बीमार होते भारतीय लोकतंत्र की मौजूदा स्थिति को पलटने का सही तरीका यही है कि समाज अपने सारे टेस्ट यानी कम्पलीट बाडी चेकअप कराए और उससे मिलने वाली रपटों के आधार पर अपना इलाज कराए। समाज के कम्पलीट बाडी चेकअप का मतलब है 2021 में जाति जनगणना। जाति जनगणना के बिना न तो समाज की सारी बीमारियों का ठीक से पता चल सकता है और जब बीमारी का पता ही नहीं चलेगा तो इलाज कैसे होगा।

संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर ने भारत की जनता की ओर से उसे एक नया संविधान देते हुए कहा था कि आज से हम एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं। जहां बालिग मताधिकार और एक व्यक्ति एक वोट के आधार पर राजनीतिक बराबरी तो कायम कर दी गई है लेकिन सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र नहीं है। अगर हम सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र नहीं ला पाए तो राजनीतिक लोकतंत्र को कायम रख पाना मुश्किल हो जाएगा। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का मतलब है घर परिवार, राजनीति और आर्थिक क्षेत्र में होने वाले निर्णयों में देश की व्यापक आबादी की हिस्सेदारी।

यह तभी संभव है जब उसे अवसर की समानता मिले और उत्पादन प्रणाली और व्यवस्था के दूसरे क्रियाकलापों से जो हासिल हो उसमें उसे हिस्सा मिले। यानी राजनीतिक लोकतंत्र सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के कंधों पर ही ठहर सकता है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक लोकतांत्रिक समाज चाहिए। अगर हम वैसा समाज नहीं बनने देंगे तो सामाजिक लोकतंत्र अपने विस्तार के लिए हिंसा करेगा। वही जो आजकल समाज में चल रही है।

जब सरकारी नौकरियां खत्म होती जा रही हैं तब आरक्षण का मामला बेमानी होकर रह जाता है। ऐसे में सकारात्मक कार्रवाई का दूसरा रास्ता ढूंढना ही होगा। वह रास्ता है निजी क्षेत्र में आरक्षण यानी डायवर्सिटी का सिद्धांत। उसकी मांग भी उदारीकरण के साथ ही चल रही है। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी

ठीक यही स्थिति समाजवाद की भी है। समाजवाद तब तक नहीं कायम हो सकता जब तक उसके लिए एक समाजवादी संस्कृति निर्मित न हो। बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार और नेशनल कौंसिल फार अप्लाइड इकानमिक रिसर्च(एनसीईएआर) के संयुक्त उपक्रम में जाति के संक्षिप्त सर्वे पर तैयार की गई पुस्तक ` कास्ट इन ए डिफरेंट मोल्ड—अंडरस्टैंडिंग द डिस्क्रिमिनेशन ' में कहा गया है, ` भारत में ज्यादातर चर्चाएं आंकड़ा विहीन स्थितियों में होती हैं। हालांकि कई मोर्चों पर स्थितियों में सुधार हुआ है लेकिन हाल के वर्षों में कई अहम कानून बिना किसी आंकड़े के ही पास किए गए हैं। इसमें शिक्षा के अधिकार और मनरेगा जैसे कानून शामिल हैं।'

पिछले तीस सालों में देश के भीतर कुछ गंभीर बहसें चल रही हैं। एक बहस मंडल आयोग की रपट के लागू होने और उसके परिणामों पर चल रही है तो दूसरी बहस उदारीकरण का हमारी आर्थिक स्थिति और लोगों के जीवन पर क्या असर पड़ा इसके बारे चल रही है। मंडल आयोग की रपट सन 1931 की जनगणना के आधार पर जो आंकड़े उपलब्ध थे, उसके बिना पर तैयार की गई थी। उसमें कहा गया था कि भारत में अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी 52 प्रतिशत है।

भारत के ज्यादातर समाजशास्त्री, राजनीतिज्ञ और पत्रकार उसी आंकड़े के आधार पर बहस करते हैं। उसी पुराने और दोषपूर्ण आंकड़ों के आधार पर नीतियां बनती हैं और उसी के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों को आपस में लड़ाया जाता है।

एक ओर कहा जाता है कि अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी 52 नहीं 41 प्रतिशत है और ज्यादा आबादी बताकर राजनीतिक दबाव पैदा किया जा रहा है।

जाति जनगणना का इतिहास

जाति आधारित जनगणना आखिरी बार 1931 में हुई थी। दस साल बाद जब फिर मौका आया तो द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा था और जनगणना ही नहीं हो सकी।

आजाद भारत में जाति जनगणना की मांग उठती रही। लेकिन कांग्रेस की सरकार उसे खारिज करती रही। सिर्फ अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यकों की गिनती होती रही।

1953 में दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर उर्फ काका कालेलकर की अध्यक्षता में पिछड़ी जातियों की स्थिति के आकलन के लिए आयोग बना। उन्होंने 1955 में जो सुझाव दिया उसका पहला बिंदु यही था कि 1961 में जो जनगणना कराई जाए उसमें जातियों और विशेष कर अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों की संख्या गिनी जाए।

लेकिन तत्कालीन नेहरू सरकार ने उनकी मांगों को ठुकरा दिया। उन्होंने अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने की भी मांग की थी लेकिन सरकार ने उसे भी नहीं माना।

सरकार का कहना था कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यकों की संख्या गिनने तक तो मामला ठीक है लेकिन उससे आगे गिनती करने से समाज में जातिवाद बढ़ने का खतरा है।

अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की मांग निरंतर तेज होती गई और उस मांग को दक्षिण भारत में द्रविड़ मुनेत्र कषगम के नेता रामास्वामी नाइकर उर्फ पेरियार और सी अन्नादुराई ने जोरदार ढंग से उठाया तो उत्तर भारत में डा राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में समाजवादियों ने नारा ही दिया कि `सोशलिस्टों ने बांधी गांठ पिछड़ा पावै सौ में साठ'।

जब 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी और उसके गठन में समाजवादी नेताओं की प्रमुख भूमिका रही तो उसने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बिंध्येश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया। उस आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में पिछड़ा वर्ग की आबादी को 52 प्रतिशत(1931 की जनगणना के आधार पर) मानते हुए अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने का सुझाव दिया।

आयोग ने कहा कि देश में पिछड़ी जातियों की आबादी को जानने के लिए जाति जनगणना होना बहुत आवश्यक है। लेकिन न तो रपट लागू हुई और न ही जाति की जनगणना हुई।

जब 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी तब तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने शरद यादव और रामविलास पासवान जैसे पिछड़े और दलित नेताओं के दबाव में उसे लागू किया।

सन 1995 में पिछड़ा वर्ग आयोग ने सुझाव दिया कि सन 2001 की जनगणना में पिछड़ा वर्ग के जाति और समुदायवार आंकड़े इकट्ठे किए जाएं। लेकिन सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया। इस तरह 2001 की जनगणना भी पिछड़ी जातियों की वास्तविक गिनती के बिना पूरी हो गई।

सन 2006 में सुमित्रा महाजन

सामाजिक न्याय और सबलीकरण आयोग की संसद की स्थायी समिति की अध्यक्ष बनीं और उन्होंने भी कहा कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए।

2008 में योजना आयोग ने एक प्रस्ताव पास कर सुझाव दिया कि 2011 की जनगणना में ओबीसी जातियों की गिनती को शामिल किया जाए क्योंकि इससे विकास संबंधी नीतियां बनाने में सुविधा होती है। भारत के राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य के तौर पर इस प्रस्ताव पर गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के भी हस्ताक्षर हैं।

2010 में जब नासिक के सांसद समीर भुजबल ने लोकसभा में अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों की जनगणना पर एक निजी सवाल उठाया तो उनके समर्थन में 100 ओबीसी सांसद आ गए। इस बारे में सदन में जो प्रस्ताव लाया गया उसके समर्थन में जो प्रमुख नेता खड़े हुए उनमें जनता दल(यू) के नेता शरद यादव, राजद के प्रमुख लालू प्रसाद, समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव, भाजपा के सदन के उपनेता गोपीनाथ मुंडे, कांग्रेस के मंत्री वीरप्पा मोइली, और राष्ट्रीय लोकदल के नेता अजित सिंह शामिल थे। उसके परिणाम स्वरूप 2011 में अन्य पिछड़ी जातियों की सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना कराई गई।

लेकिन ग्रामीण विकास मंत्रालय और आवास व शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय ने एसईसीसी 2011 के आंकड़ों को अंतिम रूप दिया और उसमें से जाति के आंकड़े निकालकर उसे जारी कर दिया। हालांकि 2011 के जाति जनगणना के आंकड़ों को जमा करने के लिए कर्मचारियों और दूसरे संसाधनों की व्यवस्था भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त ने की थी।

मोदी सरकार ने कहा कि आंकड़ों में गड़बड़ियां हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष और जाने माने अर्थशास्त्री अरविंद पनगढ़िया के नेतृत्व में 2015 में एक पैनल बना और उसने आंकड़ों को जांच परख कर उसे दुरुस्त किया। लेकिन उसके बाद भी सरकार ने आंकड़ें जारी नहीं किए।

भाजपा सांसद गणेश सिंह के नेतृत्व में ओबीसी कल्याण संबंधी संसद की स्थायी समिति ने भी 2020 में सुझाव दिया कि जातियों की जनगणना कराई जानी चाहिए। सन 2021 में पिछड़ी जातियों के राष्ट्रीय आयोग ने भी सरकार को सुझाव दिया कि वह सुप्रीम कोर्ट में जाति जनगणना की मांग करने वाली एक याचिका पर चल रही सुनवाई के दौरान जाति जनगणना का समर्थन करने वाला हलफनामा लगाए।

दूसरी ओर कहा जाता है कि वह आबादी तो 60 प्रतिशत तक है। सवर्ण राजनीति के दबाव में उसे कम करके दिखाया जाता है। इसी के साथ यह भी राजनीतिक खेल चलता रहता है कि अन्य पिछड़ी जातियों में से कुछ जातियां बाकी जातियों का हिस्सा हड़प ले रही हैं। इसी बिना पर भारतीय जनता पार्टी इस वर्ग के भीतर विभाजन करके उसे अपनी ओर खींच रही है।

लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों को अपनी ओर खींचने की इस योजना में धर्म और जाति की मिथकीय कथाओं को आधार बनाया जा रहा है। साथ ही उन्हें कुछ राजनीतिक पदों से उपकृत करके पूरे आख्यान को चलाया जा रहा है।

जबकि जातियों के पिछड़ापन के पीछे पिछले तीस सालों में उभरी वह कारपोरेट व्यवस्था भी जिम्मेदार है जिसने एक ओर याराना पूंजीवाद को जन्म दिया है तो दूसरी ओर दस्तकारी और हस्तशिल्प और ग्रामीण उद्योग के उन तमाम पारंपरिक व्यवसायों को खत्म कर दिया है जिन पर अन्य पिछड़ी जातियों का बड़ा हिस्सा निर्भर था।

हालांकि कुछ विद्वानों का यह भी कहना है कि उदारीकरण के साथ हमारी अर्थव्यवस्था उस समाजवादी दिखावे से मुक्त हुई है जिस पर प्रत्यक्ष रूप से सवर्णों का ही कब्जा था।

अब दलित और पिछड़े उद्यमी खड़े हो रहे हैं और उन्हीं के साथ तमाम प्रोफेशनल भी आगे आ रहे हैं। रोजगार के नए अवसर भी बन रहे हैं। बीटी राजशेखर जैसे दलित बौद्धिकों का यही तर्क है कि समाज की दबी कुचली जातियों को उदारीकरण से लाभ हुआ है और सवर्ण जातियों का वर्चस्व टूटा है। जबकि कांचा इलैया जैसे बौद्धिक मानते हैं कि उनके पारंपरिक व्यवसायों को

नुकसान पहुंचा है। उनमें तमाम लोग गरीब हुए हैं।

जाति जनगणना के माध्यम से इस बहस के लिए पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध होंगे और तब जो भी नीतियां बनेंगी वे वस्तुगत तरीके से बनेंगी और उन पर धर्म आधारित सांप्रदायिक राजनीति या जाति के मिथकों पर आधारित जातिवादी राजनीति का मुलम्मा नहीं चढ़ाया जा सकेगा।

जाति जनगणना के माध्यम से इस बहस के लिए पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध होंगे और तब जो भी नीतियां बनेंगी वे वस्तुगत तरीके से बनेंगी

इसी के साथ यह सच्चाई भी सामने आएगी कि सरकारी नौकरियों में निरंतर कटौती और सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण के साथ ही कितनी नौकरियां कम हुई हैं। वे ऐसे क्षेत्र थे जहां अन्य पिछड़ा वर्ग या समाज के अन्य वर्गों को भी रोजगार मिल सकता था।

जब सरकारी नौकरियां खत्म होती जा रही हैं तब आरक्षण का मामला बेमानी होकर रह जाता है। ऐसे में सकारात्मक कार्रवाई का दूसरा रास्ता ढूंढना ही होगा। वह रास्ता है निजी क्षेत्र में आरक्षण यानी डायवर्सिटी का सिद्धांत। उसकी मांग भी उदारीकरण के साथ ही चल रही है। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेकिन वह तभी हो पाएगा जब जाति की सामाजिक और आर्थिक स्थिति के आंकड़े उपलब्ध होंगे।

इसके अलावा जातियां सिर्फ हिंदू समाज में नहीं हैं। वह मुस्लिम समाज में भी हैं और भारत के अन्य धार्मिक समाजों में भी हैं। वहां भी अशराफ जातियों के विरुद्ध अजलाफ जातियां अपनी हिस्सेदारी मांग रही हैं। पसमांदा समाज का आंदोलन ऐसा ही आंदोलन है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं 2017 में उड़ीसा के भाजपा सम्मेलन में इस बात पर जोर देकर कहा था, ` मुसलमानों और दूसरे धर्मों में भी ओबीसी हैं। ओबीसी के लिए दिए गए फायदे मुस्लिम ओबीसी को भी मिलने चाहिए। इन कल्याणकारी उपायों को सैयद और पठान हड़प लेते हैं।' लेकिन मामला सिर्फ हड़प लेने का नहीं है। मामला जाति की सही जनसंख्या की जानकारी होने का है। जब वह जानकारी ही नहीं रहेगी तो ओबीसी को लाभ देने की बात महज चुनावी शिगूफा बन कर रह जाएगी।

जातिगत, लैंगिक और आर्थिक असमानताएं महज पूंजीवादी विकास से नहीं टूटेंगी। कारपोरेट पूंजीवाद तो उत्पादन के नए साधनों का आविष्कार करता रहेगा तो आर्टीफिशियल इंटेलीजेंस के माध्यम से बेरोजगारी पैदा करता रहेगा।

महामारी पड़ने और अकाल पड़ने पर कभी दवाइयां तो कभी राशन बांट देगा। लेकिन वह बढ़ती हुई सामाजिक आर्थिक खाई की ओर ध्यान नहीं देगा। वह सामाजिक दासता और बाल देह व्यापार जैसी सामाजिक बुराई

और हिंसा को महज कानूनी मसला मान कर पुलिस दमन से उसका हल निकालना चाहेगा। वह नहीं मानेगा कि तमाम ऐसी जातियां हैं जो औपचारिक व्यवस्था से आज भी बाहर हैं।

सामाजिक असमानता और कट्टरता की इन्हीं त्रासद स्थितियों की जटिलताओं की ओर संकेत करते हुए डा राम मनोहर लोहिया ने वर्ण और योनि के कटघरे नामक अपने व्याख्यान में कहा था, ` जो लोग सोचते हैं कि आधुनिक आर्थिक ढांचे के जरिए गरीबी

फोटो स्रोतः गूगल

मिट जाने पर यह कटघरे अपने आप टूट जाएंगे वे बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं।

गरीबी और ये कटघरे एक दूसरे के पैदा किए हुए कीड़ों पर पलते हैं। गरीबी के खिलाफ लड़ने की सारी कोशिशें झूठी हैं अगर साथ ही साथ इन दोनों कटघरों के खिलाफ सचेत होकर लड़ाई नहीं लड़ी जाती।'

यह सही है कि भारत के सामंतवाद, कारपोरेट पूंजीवाद और उसके साथ गठजोड़ बनाकर बैठे हिंदुत्ववाद (ब्राह्मणवाद) से छुटकारा महज जाति आधारित जनगणना से नहीं मिल पाएगा।

लेकिन जाति जनगणना एक प्रकार की डायग्नोसिस है जिससे समाज के बारे में सही दवाई ढूंढी जा सकेगी यानी नीतियां बनाई जा सकेंगी। जाति जनगणना को रोकने में उच्च वर्णों के भीतर पलने वाली सांप्रदायिक राजनीति सबसे आगे रहती है।

यही वजह है कि अंग्रेजी शासन के दौरान जाति जनगणना का विरोध करने में हिंदू महासभा और मुस्लिम जमींदारों की विभाजनकारी पार्टी मुस्लिम लीग सबसे आगे थीं। उनका कहना था कि जाति की जगह पर धर्म लिखवाओ। आज भारत को अगर असमान व्यवस्था से निकालकर बराबरी और भाईचारे की व्यवस्था का निर्माण करना है तो उसके लिए जाति की जनगणना जरूरी है और इसी से लोकतंत्र को बचाने का मार्ग भी निकलेगा।

(यह लेखक के अपने विचार हैं)

यूपी में जंगलराज

दि प्रिंट
होम राजनीति देश डिफेंस एजुकेशन हेल्थ अर्थजगत विदेश मत-विमत
लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलने, गोली मारकर हत्या के आरोप में मंत्री अजय मिश्रा के बेटे पर केस दर्ज
कानपुर के कारोबारी की मौत
पिता की मौत पर बेटे को क्या दूंगी जवाब, मुझे इंसाफ चाहिए
चार साल के मासूम बेटे को गोद में लिए मनीष की पत्नी मीनाक्षी बोलीं, पुलिस वालों ने पति को मार डाला
उठाया सवाल, किस कानून के तहत पुलिस रात में गई थी चेकिंग करने, क्या ऐसे ही सुरक्षा करती है पुलिस
दैनिक भास्कर
जालिम पुलिस ने परिवार बिखेर दिया
पुलिसकर्मियों पर हत्या का आरोप
कानपुर
उत्तर प्रदेश
लखीमपुर खीरी केस: सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी, पूछा- 302 में क्यों नहीं हुई गिरफ्तारी, यूपी सरकार को फटकार
लखीमपुर खीरी कांड में किसानों समेत 8 लोगों की मौत, मंत्री के बेटे पर कुचलने का आरोप
Updated on 10/3/2021

बुलेटिन ब्यूरो

भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश अपराधों की आग में झुलस रहा है। कानून का कोई खौफ नहीं। अपराधी तो अपराध कर ही रहे, भाजपा राज में पुलिस भी अपराधियों की तरह आचरण कर रही। गोरखपुर में पुलिस के उत्पीड़न से कानपुर के एक व्यापारी की मौत इसकी बानगी है।

सत्ता के संरक्षण में आपराधिक गतिविधियां हो रही हैं, इसका उदाहरण है लखीमपुर में किसानों को गाड़ी से कुचल कर मार डालना। जिसका आरोप केंद्र में गृह राज्य मंत्री के बेटे पर है। यूपी में सत्ता और अपराध के गठबंधन एवं पुलिस के उसमें हिस्सेदार बन जाने से जंगलराज कायम हो गया है। जनता त्राहि-त्राहि कर रही है।

उत्तर प्रदेश में जबसे भाजपा सरकार आई है अपराधियों का भाग्य निर्णय भी जाति-धर्म देखकर किया जाने लगा है। हालात यह हैं कि व्यापारी से वसूली के मामले में हत्या का आरोपी एक आईपीएस अधिकारी पिछले एक साल से फरार है। उसकी गिरफ्तारी हुई तो कई बड़ों के राज खुल जाएंगे। लिहाजा सरकार के कहने पर पुलिस उसे गिरफ्तार ही नहीं कर रही।

भाजपा के राज में ठोको पुलिस जनता की रक्षा के बजाय फर्जी केस बनाने और फर्जी एनकाउंटर करने में लगी है। इसका फायदा उठाकर अपराधी बेखौफ हत्या, लूट, अपहरण और दुष्कर्म की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। मुख्यमंत्री अपने जुमलों में रोज अपराधों पर जीरो टॉलरेंस की बातें करते रहते हैं पर कोई उनको सुनता नहीं है। भाजपा सरकार में मंत्री से लेकर अधिकारी तक सब अपनी मनमानी कर रहे हैं किसी का किसी पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया है।

खुद मुख्यमंत्री की निरंतर मौजूदगी में भी गोरखपुर अपराधियों का अड्डा बन गया है। मुख्यमंत्री आए दिन गोरखपुर जाते रहते हैं लेकिन अपराध नियंत्रण करने में बेबस नज़र आते हैं। जब जिला ही नहीं संभल रहा है तो देश का सबसे बड़ा प्रदेश कैसे संभल पाएगा?

भाजपा राज में कानून-व्यवस्था का आलम यह है कि न सिर्फ आम लोग बल्कि साधु-संतों की जिंदगी भी खतरे में है। उन पर जानलेवा हमलों की सूची लम्बी है। बीते 4 सालों में 42 साधु संतों की हत्या हो चुकी है। किसी को गोली मारी गई तो किसी की संदिग्ध स्थितियों में मौत हुई। अभी तक किसी को न्याय नहीं मिल पाया है।

हाल के दिनों में सहारनपुर में सत्ता संरक्षित दबंगों ने दंपति को जिंदा फूंक दिया। कानपुर में दुष्कर्म के बाद युवती को 10वीं मंजिल से फेंक दिया गया। बुलन्दशहर में किशोरी से दुष्कर्म हुआ। गोण्डा में एक दिन में दो विवाहिताओं की दिल दहलाने वाली हत्यायें हो गई। अलीगढ़ में अपहरण की घटना हुई। उन्नाव, शाहजहांपुर और हाथरस की पीड़िताओं के साथ कैसा सलूक हुआ यह सबने देखा।

यूपी का हाल

रक्षक ही भक्षक

बुलेटिन ब्यूरो

उत्तर प्रदेश में भाजपा के शासन में कानून-व्यवस्था की स्थिति किस कदर बदतर हो चुकी है इसकी बानगी 27-28 सितंबर की रात सूबे के मुख्यमंत्री के गृह नगर गोरखपुर में देखी गई। गोरखपुर की पुलिस ने वहां एक होटल में ठहरे कानपुर के व्यवसायी मनीष गुप्ता की पीट-पीट कर हत्या कर दी। हत्या के आरोपी पुलिस वाले कई दिन फरार रहने के बाद गिरफ्तार किए जा सके।

मृतक व्यवसायी की पत्नी के आरोपों से प्रदेश में कानून-व्यवस्था के मोर्चे पर रामराज होने के भाजपाई दावों की पोल खुल चुकी है। पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। जिसमें उन्होंने मामले की जांच सीबीआई को ट्रांसफर करने की मांग की है। उन्होंने कोर्ट से कहा है कि उन्हें यूपी पुलिस की एसआईटी जांच पर भरोसा नहीं है। दरअसल मनीष गुप्ता के साथ जो घटना घटी उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। यह घटना दुःखद और अकल्पनीय है। भाजपा सरकार में पुलिस का स्तर संवेदना के शून्य स्तर से भी नीचे जा चुका है।

गोरखपुर में पुलिस द्वारा व्यवसायी की हत्या जैसी घटना देश-दुनिया में नहीं हुई। यह कुछ ऐसा ही है कि कोई अपने घर में सो रहा हो, या शहर से बाहर जाने पर होटल में ठहरा तो पुलिस आएगी, दरवाजा खुलवाएगी, कमरे में घुसकर इतना मारेगी की जान चली जाएगी। यह पुलिस को कानून के दायरे में

सभी फोटो : गूगल

रहते हुए कानून-व्यवस्था बनाए रखने की हिदायत देने के बजाय उसे ठोक दो की खुली छूट देकर इतराने के सरकारी रवैए का नतीजा है।

इस अतिवादी रवैए ने पुलिस को रक्षक की जगह भक्षक बना दिया है। सबसे ज्यादा हिरासत में मौतें यूपी में हो रही हैं। मानवाधिकार हनन की सबसे ज्यादा नोटिस यूपी सरकार को मिली है। यूपी में हत्या और अन्य अपराधिक घटनाओं के बाद पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिलता है।

भाजपा राज में पुलिस की बर्बरता की कई घटनाएं हो चुकी हैं। इन मामलों में पुलिस-प्रशासन को कार्रवाई करने का निर्देश देने के बजाय सरकार ने अफसरों को मामला दबा देने में जुट जाने और झूठ बोलने के काम में लगाया। तभी तो आला अधिकारियों द्वारा पीड़ित पक्ष को ही धमकाने या मैनेज करने के कई वाकए सामने आए। यहां तक की गोरखपुर के व्यवसायी हत्या कांड में भी परिजनों को केस न दर्ज करवाने के लिए मनाते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के वीडियो सामने आए। इससे पहले पंचायत चुनावों में पुलिस ने विपक्षी प्रत्याशियों के पर्चे छीने। भाजपा जब पुलिस और डीएम से गलत काम कराएगी तो अंजाम यही होगा।

किसानों पर भाजपाइयों ने चढ़ाया चक्का

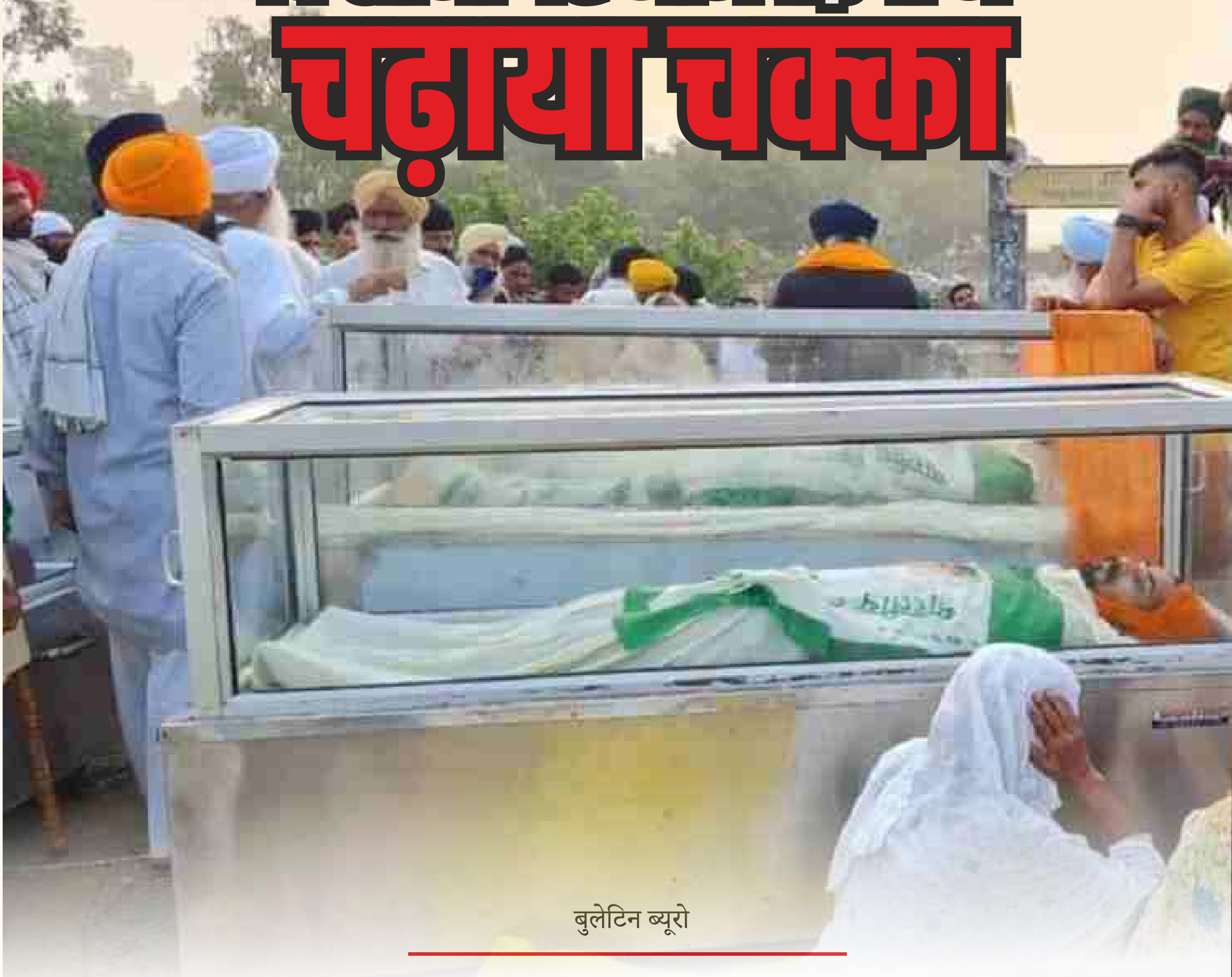

बुलेटिन ब्यूरो

जो करतूत क्रूर अंग्रेज शासक भी न कर सके वह मानवता की दुहाई देने वाले भाजपाइयों ने कर दिखाया। सत्ते के नशे में चूर भाजपाइयों ने लखीमपुर खीरी में शांतिपूर्ण तरीके से सड़क पर जा रहे किसानों को जीप से कुचल कर मार डाला। उसका आरोप केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री व लखीमपुर खीरी के सांसद के बेटे और उसके दोस्तों पर है।

समाजवादी पार्टी के लगातार दबाव से गिरफ्तारियां तो हुईं लेकिन गृह राज्य मंत्री को पद पर बनाए रखा गया है। जिनके पद पर रहते निष्पक्ष जांच असंभव है। उल्लेखनीय है कि किसानों को कुचले जाने के कुछ दिन पहले ही इन मंत्री महोदय ने खुले मंच से धमकी दी थी कि किसानों ने कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन न खत्म किया तो वे उन्हें अपनी ताकत दिखा देंगे।

दरअसल किसानों को कुचलने की भाजपाई मानसिकता उसके किसान विरोधी रवैए का ही अंजाम है। भाजपा सरकार किसानों को लगातार अपमानित कर रही है। अब तो तानाशाही तरीके से भाजपा किसानों की हत्या पर उतारू हो गई है। पिछले 10 माह से अपनी मांगों में लेकर आंदोलन कर रहे किसानों की भाजपा सरकार सुनवाई नहीं कर रही है। इससे किसानों का आक्रोशित होना स्वाभाविक है।

प्रदेश किसानों का है लेकिन किसान यहां सबसे ज्यादा अपमानित और पीड़ित है। उनसे कहा गया था कि आय दोगुनी होगी लेकिन वह भी छीन ली गई। किसानों को

लखीमपुर खीरी में गाड़ियों से कुचल दिया गया। अगर भाजपा को नहीं हटाया गया तो यह उन्हें टायरों से संविधान को कुचल देंगे। भाजपा के लोगों ने किसानों को कभी मवाली तो कभी आतंकवादी कहा। अर्थव्यवस्था में ग्रामीण कृषि का प्रथम स्थान आता है लेकिन भाजपा राज में गांव पूर्णतया उपेक्षित हैं। खेती-किसानी बर्बाद है। वस्तुतः भाजपा कृषि की स्वतंत्रता समाप्त कर उसे उद्योग बनाने का साजिश कर रही है। किसान हितों की उपेक्षा करना भाजपा के चरित्र में है। भाजपा राज में किसान नहीं पूंजी घरानों को संरक्षण मिलता है। उसकी कृषि नीति इसीलिए किसान के बजाय पूंजीघरानों और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के हितों को आगे बढ़ाती है। तीन कृषि कानून इसके स्पष्ट उदाहरण हैं। एमएसपी की अनिवार्यता की मांग पर भाजपा सरकार इसलिए ढुलमुल रवैया अपना रही है।

भाजपा की किसान विरोधी नीतियों के चलते कृषि में उपयोग आने वाली चीजें महंगी हो रही है। सिंचाई में काम आने वाला डीजल महंगा हो गया है। बिजली महंगी हो गई है। कीटनाशक, बीज, दवा, खाद सभी मंहगी है। इससे कृषि उत्पादों की लागत स्वभाविक रूप से बढ़ी है जबकि किसान को लागत मूल्य भी फसल बिक्री से नहीं मिल पाता है।

अखिलेश ने सड़क पर उतर कर सरकार को ललकारा

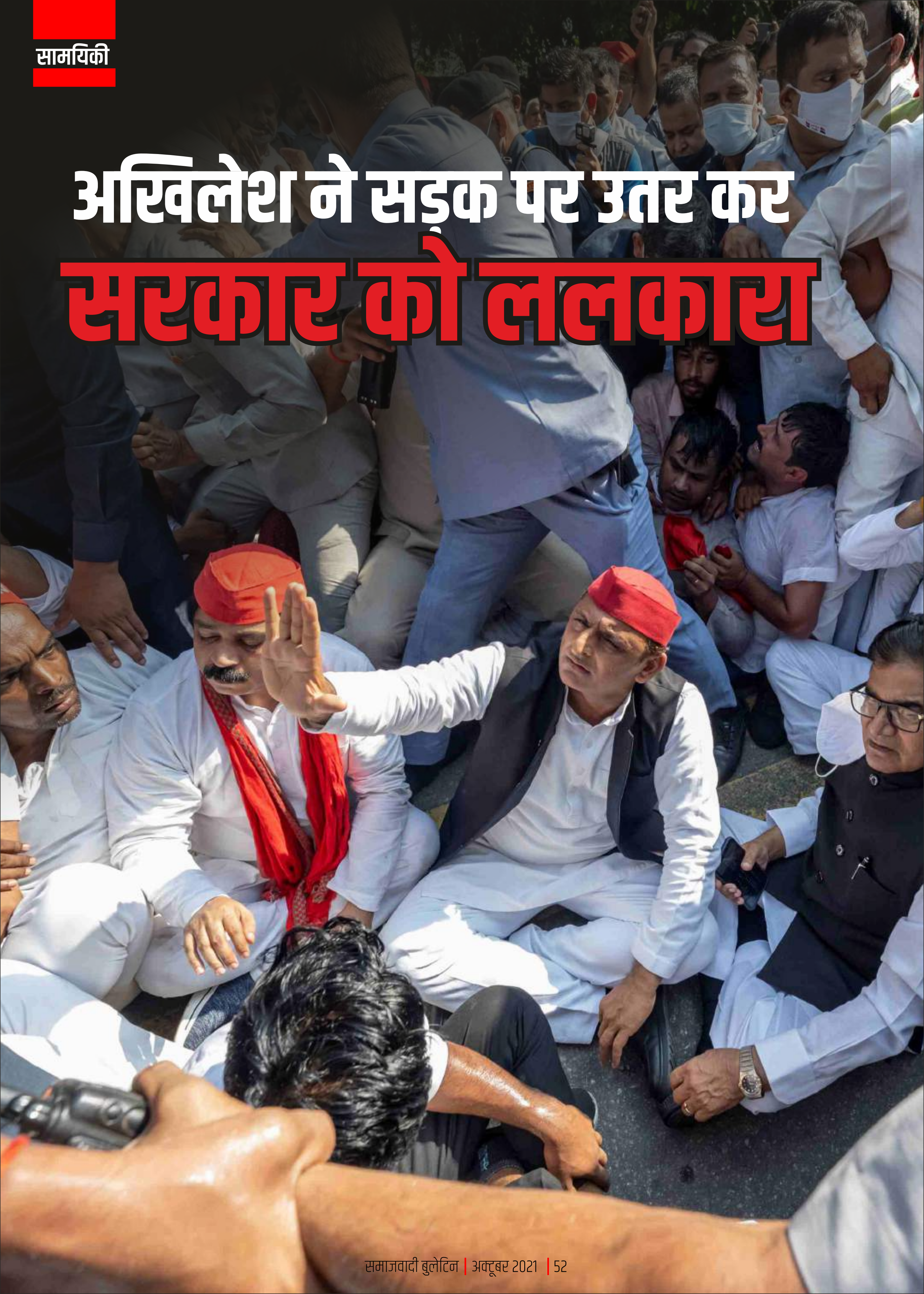

बुलेटिन ब्यूरो

लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या से शोकाकुल परिवारों से मिलकर सांत्वना देने के लिए 4 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी जा रहे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव को रोकने के लिए पुलिस ने उनके आवास ने छावनी में तब्दील कर दिया। आवास के बाहर पुलिस ने भारी किलेबंदी। इसके बावजूद श्री अखिलेश यादव वे आवास से बाहर निकलने से वे रोक नहीं सके।

लखीमपुर कांड के विरोध में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने समाजवादियों के साथ सड़क पर उतर कर लखीमपुर न जाने दिए जाने के विरोध में जबरदस्त धरना प्रदर्शन किया। लोकतांत्रिक तरीके से सड़क पर बैठ कर धरना दिया जाना भी लोकतंत्र विरोधी यूपी सरकार तो रास न आई। लिहाजा पुलिस ने श्री अखिलेश यादव को गिरफ्तार कर लिया। अपने नेता को आवास पर ही अवैध तरीके से रोकने की पुलिस की कोशिश और फिर उनकी गिरफ्तारी से पूरे प्रदेश में कार्यकर्ताओं में उबाल आ गया।

श्री अखिलेश यादव के आवास के सामने आज तड़के से ही पुलिस ने घेरा डाल रखा था। श्री यादव जब लखीमपुर-खीरी जाने के लिए निकले तो उन्हें पुलिस अधिकारियों ने रोकने की कोशिश की। तब तक बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी वहां आ गए थे। श्री यादव के न रूकने पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर ईको गार्डेन ले जाया गया जहां उनके साथ तमाम पार्टी नेता, कार्यकर्ता भी गिरफ्तारी देने के लिए जमा हो गए। उनके साथ

समाजवादी पार्टी के प्रमुख महासचिव प्रो. रामगोपाल यादव कई अन्य वरिष्ठ नेता और विधायक भी थे।

श्री अखिलेश यादव और प्रो. रामगोपाल यादव की गिरफ्तारी की सूचना मिलते ही पूरे प्रदेश में आक्रोश आ गया। सपा कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। जगह-जगह विरोध व धरना-प्रदर्शन होने लगे। समाजवादी पार्टी ने सभी जिला मुख्यालयों पर इस घटना के विरोध में धरना-प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। कई स्थानों पर कार्यकर्ताओं ने सरकार का पुतला फूंका। पुलिस से कई स्थानों पर झड़पें हुई।

आंदोलित सपा कार्यकर्ताओं का कहना था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव की गिरफ्तारी भाजपा की तानाशाही तथा अलोकतांत्रिक रवैया है। उन्होंने कहा कि सपा के प्रमुख महासचिव प्रो. राम गोपाल यादव सहित कई जनप्रतिनिधियों की गिरफ्तारी असंवैधानिक है। भाजपा सरकार कानून का शासन स्थापित करने में पूरी तरह विफल रही है। कानून व्यवस्था ध्वस्त है। भाजपा तानाशाही कर रही है। जनता की आवाज दबाई जा रही है। सरकारी मशीनरी विपक्ष का दमन कर रही है। पुलिस प्रशासन सरकार का मोहरा बन गया है।

श्री अखिलेश यादव ने कहा कि किसानों के साथ जुल्म हो रहा है। सरकार सच सामने नहीं आने देना चाहती। किसानों पर इतना अत्याचार और उत्पीड़न कभी नहीं हुआ

श्री अखिलेश यादव ने मीडिया से कहा कि किसानों के साथ जुल्म हो रहा है। सरकार सच सामने नहीं आने देना चाहती। किसानों पर इतना अत्याचार और उत्पीड़न कभी नहीं हुआ जितना भाजपा सरकार कर रही है। उन्होंने पूरे मामले में केन्द्रीय गृहराज्य मंत्री और उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए उपमुख्यमंत्री केशव मौर्य के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि किसानों की हत्या हुई है, दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले। श्री

यादव ने मांग की कि दोषियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हो, पीड़ित किसानों के परिजनों को दो-दो करोड़ रुपए मुआवजे में दिये जाए तथा घर के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए।

श्री यादव ने कहा कि विपक्ष के नेताओं को किसानों के परिजनों से मिलने से रोकना हिटलरशाही है। आय दोगुनी करने का वादा करने वाली यह सरकार असफल है। उन्होंने कहा कि किसानों के खिलाफ भाजपा काला कानून क्यों लाई है? सरकार के लोग किसानों को आतंकवादी और मवाली कहकर अपमानित कर रहे हैं। हम अन्याय और उत्पीड़न के खिलाफ जाना चाहते है तो सरकार क्यों रोक रही है?

भाजपा सरकार पुलिस के माध्यम से चल रही है। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि यह सरकार आंदोलन को कुचलना चाहती है, इसलिए किसानों पर गाड़ी चढ़ाकर उन्हें कुचल दिया।

अखिलेश पहुंचे पीड़ितों के पास

बुलेटिन ब्यूरो

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने 7 अक्टूबर को **लखीमपुर खीरी** पहुंचकर सत्ताधीशों के नरसंहार तिकोनिया कांड के पीड़ित पत्रकार और किसान परिवारों से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की और कुचलकर मारे गए पत्रकार और किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित की।

पलिया में मृतक किसान लवप्रीत, निघासन में पत्रकार रमन कश्यप और धौरहरा के लहबड़ी थाना क्षेत्र में नक्षत्र सिंह के परिजनों से मिलने के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने कहा कि पीड़ित परिवार न्याय चाहते हैं। सरकार के अन्दर अहंकार ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट से ही गरीबों की मदद होगी। सच्चाई सामने आएगी। समाजवादी पार्टी पीड़ित परिजनों के साथ है। समाजवादी सरकार बनने पर पीड़ितों की ज्यादा से ज्यादा मदद होगी।

अपने लखनऊ आवास से लखीमपुर खीरी के लिए निकलने से पहले मीडिया से बात करते हुए श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार को कुछ नज़र नहीं आ रहा है। उसको सत्ता के दंभ का मोतियाबिंद हो गया है। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि लखीमपुर खीरी घटना की सिटिंग जज से

न्यायिक जांच हो तभी पीड़ित किसान परिवारों को न्याय मिलेगा।

श्री यादव ने कहा कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अपने पद से इस्तीफा क्यों नहीं देते हैं? घटना का आरोप गृह राज्य मंत्री के बेटे पर है। क्या उनके पद पर रहते हुए पीड़ित किसान परिवारों को न्याय मिलेगा? श्री अखिलेश यादव ने कहा कि घटनाओं के बाद पहले दिन से ही भाजपा के लोग मुद्दों में उलझाने में लग जाते हैं।

इसके अगले दिन, 8 अक्टूबर को श्री अखिलेश यादव ने लखीमपुर खीरी के तिकोनिया कांड के शहीद परिवारों से **बहराइच** जाकर मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी और उन्हें हर सम्भव मदद तथा न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। श्री यादव रघुनाथपुर महुरनिया के गुरविंदर सिंह, नानपारा के श्री दलजीत सिंह के परिवारजनों से मिले। उन्होंने कहा परिवार न्याय चाहता है उसे सुरक्षा मिलनी चाहिए।

श्री अखिलेश यादव ने कहा कि लखीमपुर कांड के बाद पूरे देश में किसानों के बीच भावात्मक एकता जन्मी है

श्री अखिलेश यादव ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात के बाद कहा किलखीमपुर हत्याकांड के बाद जिस तरह पूरे देश-विशेषकर उत्तर प्रदेश में किसानों के बीच भावात्मक एकता जन्मी है, वह अभूतपूर्व है। ये सरकार लोकतंत्र का गला घोंट रही है। गांवों में भाजपा के झंडे उतर गए हैं।

श्री यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी न्याय के लिए लड़ती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद न्याय की उम्मीद जगी है। सुप्रीम कोर्ट को भी उत्तर प्रदेश सरकार के रवैये पर भरोसा नहीं है। श्री यादव ने बहराइच जाने से पहले लखनऊ में मीडिया से बात करते हुए घटना में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि मंत्री रहते उनसे और उनके परिवार से कैसे पूछताछ हो सकती है। पुलिस उनके घर आएगी तब सैल्यूट करेगी और घर से जाएगी तब सैल्यूट करेगी। ऐसी पुलिस कौन सी पूछताछ करेगी? अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार सच को दबाना और सब कुछ छुपाना चाहती है।

इससे पहले श्री अखिलेश यादव ने 30 सितंबर तो कानपुर जाकर पुलिस उत्पीड़न के कारण **गोरखपुर कांड** में जान गंवाने वाले कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की पत्नी

श्रीमती मीनाक्षी गुप्ता तथा उनके परिजनों से मिलकर उनका दर्द बांटा। उन्होंने श्री गुप्ता की गोरखपुर में पुलिस की बर्बर पिटाई से मौत को दुःखद बताते हुए शोक संतप्त परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त की।

श्री अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की ओर से मृतक की पत्नी को 20 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की। उन्होंने सरकार से पीड़ित परिवार को 2 करोड़ रूपये की मदद तथा मृतक की पत्नी को क्लास टू या क्लास थ्री की नौकरी देने के लिए कहा। उन्होंने कहा पीड़ित परिवार को सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की है।

शोकग्रस्त परिवार से मुलाकात के बाद मीडिया से श्री अखिलेश यादव ने कहा भाजपा सरकार में पुलिस सुरक्षा नहीं कर रही है, वह लोगों की जान ले रही है। उत्तर प्रदेश में पुलिस का ऐसा व्यवहार किसी की सरकार में देखने को नहीं मिला। भाजपा राज में ऐसी घटनाएं लगातार हो रही है। भाजपा सरकार में पुलिस लगातार हत्या और लूट में शामिल है। इस सरकार की नीयत ही साफ नहीं है। पुलिस हिरासत में मौतें हो रही हैं। मानवाधिकार आयोग ने सबसे ज्यादा नोटिस दी हैं।

अखिलेश को सुनने उमड़ रहे लोग

*समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव की बीते एक महीने के दौरान हुई तीन जनसभाओं में जबरदस्त भीड़ जुटी। उत्तर प्रदेश के तीन अलग-अलग भौगोलिक इलाकों में हुईं उनकी इन सभाओं में इलाकाई लोग उन्हें सुनने उमड़ पड़े। पश्चिमी यूपी के सहारनपुर, रुहेलखंड के शाहजहांपुर और मध्य यूपी के कन्नौज में आयोजित उनकी इन सभाओं को मिला भारी जनसमर्थन संकेत है कि प्रदेश की जनता 2022 में बदलाव के लिए तैयार बैठी है और उसने श्री अखिलेश यादव को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने का निश्चय कर लिया है। पढ़िए **विशेष रिपोर्ट:***

बाइस का चुनाव तय करेगा जनता का भविष्य

बुलेटिन ब्यूरो

सहारनपुर जनपद में 10 अक्टूबर को चौधरी यशपाल सिंह जी की 100वीं जयंती के अवसर पर आयोजित जनसभा को सम्बोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा कि यद्यपि हमारे बीच आज चौधरी साहब नहीं है फिर भी हम उन्हें इसलिए याद करते हैं कि वे लगातार किसानों-गरीबों और आम जनता की लड़ाई लड़ते रहे थे।

उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा के चुनाव जनता के भविष्य के चुनाव हैं। भाजपा चुनाव के समय कुछ भी कर सकती है, उससे सावधान रहना है। भाजपा को रोकने की जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी और जनता की है क्योंकि वे किसान की तरह संविधान भी कुचल देंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता सब जानती है। कोई भी अहंकारी बचा नहीं, जनता ने सबको सबक सिखाया है।

श्री यादव ने कहा कि भाजपा ने किसानों को कुचला, साथ ही कानून को भी कुचला गया, अब संविधान को भी कुचलने की तैयारी है। किसान अन्नदाता है, उसे अपमानित किया जाता है। मवाली और आतंकवादी बताया जाता हैं वे अब तक संघर्ष कर रहे हैं। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा राज में बढ़ती महंगाई से सभी त्रस्त हैं। पेट्रोल 100 रुपये के पार हो गया है, कीटनाशक दवाएं, खाद, महंगे हुए हैं। बिजली और सरसों का तेल महंगा हो गया है। लोगों का जीवन चलाना दूभर हो गया है। भाजपा राज में

नौजवानों का भविष्य चौपट हुआ है। उनको रोजगार नहीं मिल रहा है।

श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार राष्ट्रीय सम्पत्ति, सब बेचे जा रहे हैं। आशंका है एक दिन सरकार भी आउटसोर्स से चलाने की बात कह कर भाजपाई निकल जाएंगे। तब बाबासाहेब के संविधान में उल्लिखित अधिकारों का क्या होगा? श्री यादव ने सहारनपुर वासियों को भरोसा दिलाया कि समाजवादी सरकार बनने पर सहारनपुर जनपद को फिर से प्रगति की राह पर वापस लाएंगे।

इस अवसर पर जिलाध्यक्ष श्री रुद्रसेन चौधरी, श्री इंद्रसेन, विधायक श्री संजय गर्ग, शिवकुमार शास्त्री, कृष्ण पाल राठी, प्रमोद त्यागी, अतुल प्रधान, आशु मलिक, प्रो सुधीर पंवार, फकीर चंद गूजर, योगेश वर्मा मजाहिर राणा, राहुल भारती आदि भी मौजूद रहे।

जिसे कुर्सी का लालच वह कैसा योगी!

शाहजहांपुर की जनसभा

बुलेटिन ब्यूरो

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने 6 अक्टूबर को शाहजहांपुर के बड़ा गुरूद्वारा नानकपुरी सुनसारघाट पहुंच कर मत्था टेका और संत बाबा सुखदेव सिंह जी भूरिवालों की सालाना बरसी कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर आयोजित सम्मेलन में उन्होने सभी लोगों का आभार जताते हुए संत बाबा सुखदेव सिंह जी भूरिवालों को श्रद्धांजलि दी। उन्होने शहीद नवरीत सिंह एवं बाबा कश्मीर सिंह जी को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर स्मरण किया।

वहीं शाहजहांपुर की इन्दिरा नगर कालोनी में पहुंच कर श्री अखिलेश यादव ने पार्टी के संस्थापक सदस्य पूर्व मंत्री स्वर्गीय राममूर्ति सिंह वर्मा के चित्र पर माल्यार्पण किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने स्वर्गीय राममूर्ति सिंह वर्मा के परिजनों से मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राममूर्ति सिंह वर्मा ने लगातार पार्टी को मजबूत बनाने का काम किया। वे बहुत ही लोकप्रिय नेता थे। कई बार विधायक और लोकसभा सदस्य रहे॥ कठिन परिस्थितियों में भी गरीबों-किसानों का साथ नहीं छोड़ा।

बड़ा गुरूद्वारा नानकपुरी सुनसारघाट के सम्मेलन में श्री अखिलेश यादव ने अपने सम्बोधन में याद दिलाया कि आजादी की लड़ाई में सिख समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। सिख भाइयों ने पूरी दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ाया है। समाजवादी सरकार में सिख समाज का हमेशा से सम्मान किया है।

उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि सिर्फ गद्दी पर बैठने से कोई योगी नहीं हो जाता है। संत समाज के लोग जानते हैं क्योंकि योगी वह होता है जो मोह माया से दूर होता है। जिसे कुर्सी का लालच हो वह कैसा योगी। मुख्यमंत्री अन्याय करते हैं। योगी वह होता है जो दूसरे के दुख को अपना दुख समझे। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार अंग्रेजों के जुल्मों से भी आगे निकल गई है। किसानों की आवाज को कुचला जा रहा है। लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ जो हुआ है, ऐसा किसानों के साथ कभी नहीं हुआ। इस सरकार को हटाना जरूरी है। इस सरकार के हटने से ही किसानों, नौजवानो और सभी लोगों को न्याय मिलेगा। जो सरकार न्याय न दे पाए, धर्म में झगड़े लगाती हो, उसे हर हालत में हटाना होगा। उन्होंने कहा दिल्ली की सरकार को हटाने के लिए यूपी की सरकार को हटाना है। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि महंगाई लगातार बढ़ रही है। डीजल, पेट्रोल खाद, बीज सब महंगा हो गया लेकिन भाजपा को पता ही नहीं है।

इस अवसर पर प्रमुख संत बाबा निर्मल सिंह जी, बाबा अमरजीत सिंह, बाबा अजैब सिंह, बाबा जग्गा सिंह, माता इंद्रजीत कौर खालसा, हजूर साहेब वाले बाबा जी सरदार मंजीत सिंह, सरदार कुलदीप भुल्लर, गोपाल अग्निहोत्री, विक्रमजीत सिंह, हेमराज वर्मा रामपाल यादव, रामसरन, मनोज पारस, आर ए उस्मानी, अताउर्रहमान, डा रागनी सिंह, तनवीर खां जिलाध्यक्ष, उपेन्द्र पाल सिंह, शुभलेश यादव की विशेष उपस्थिति उल्लेखनीय रही।

सपा सरकार में मिलेगी सस्ती बिजली

कन्नौज की जनसभा

बुलेटिन ब्यूरो

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने 29 सितंबर को कन्नौज में पूर्व विधायक श्री कप्तान सिंह यादव की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने श्री कप्तान सिंह यादव को याद करते हुए कहा कि वे समाजवादी सिद्धांतों पर चलने वाले स्पष्टवादी नेता थे। उनके रहते इस क्षेत्र में समाजवादी प्रत्याशी ही जीतते रहे है। डाॅ लोहिया, नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव और स्वयं मुझे यहां की जनता ने बहुमत से निर्वाचित किया है।

श्री अखिलेश यादव के आगमन से पूर्व ही बड़ी संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग और नौजवान सभा स्थल पर एकत्र हो गए थे। मंच पर उनके पहुंचते ही जनता का जोश उमड़ पड़ा। अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारों से पूरा वातावरण गूंज उठा।

जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि समाजवादी सरकार बनने पर बिजली सस्ती होगी, नौजवानों को रोजगार मिलेगा और बड़े पैमाने पर भर्तियां होंगी। उन्होंने कहा महिलाओं के लिए समाजवादी पेंशन बढ़ाई जाएगी। समाजवादी पार्टी के चुनाव घोषणापत्र में किसानों, नौजवानों, महिलाओं के लिए तमाम योजनाएं रहेंगी।

श्री अखिलेश यादव ने कहा कि तमाम लोग समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं। भाजपा के प्रति लोगों का आकर्षण नहीं बचा है। भाजपा अपने वादे में खरी नहीं उतरी है। श्री यादव ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट है। ये सरकार गरीबों की सरकार नहीं है। समाजवादी पार्टी विकास की राजनीति करती है। भाजपा नफरत फैलाती है। भाजपा को सिर्फ वोट से मतलब है। लड़ाई बड़ी है, भाजपा तरह-तरह की साजिशें कर सकती है। बूथ स्तर पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को लड़ना होगा क्योंकि 2022 का चुनाव प्रदेश के भविष्य का भी चुनाव होगा।

इस अवसर पर सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री नरेश उत्तम पटेल, पूर्व सांसद छोटे सिंह, पूर्व सांसद तेज प्रताप, एमएलसी पुष्पराज जैन उर्फ पम्मी जैन, विधायक सोबरन सिंह, पूर्व मंत्री आलोक शाक्य, विधायक बृजेश कठेरिया भी मौजूद थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष कलीम खान ने की।

चलो सपा की ओर

लगातार बढ़ता जा रहा समाजवादी कारवां

बुलेटिन ब्यूरो

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में भरोसा करते हुए विभिन्न दलों और संगठनों का अपनी पार्टी छोड़ कर सपा में शामिल होने का सिलसिला लगातार जारी है।

दिनांक 17 अक्टूबर को श्री अखिलेश यादव की उपस्थिति में सपा के लखनऊ स्थित प्रदेश कार्यालय में बसपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व विधायक श्री आर.एस. कुशवाहा, हरि किशोर तिवारी प्रदेश अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, पूर्व सांसद श्री कादिर राणा समाजवादी पार्टी में शामिल हुये।

दिनांक 3 अक्टूबर को श्री अखिलेश यादव

के नेतृत्व में आस्था जताते हुए पूर्व सांसद तथा बसपा के राष्ट्रीय महासचिव श्री वीर सिंह एडवोकेट (मुरादाबाद), पूर्व विधायक श्री अजीम भाई (फिरोजाबाद) तथा प्रमुख समाजसेवी एवं (भाजपा) के युवा क्षेत्रीय मंत्री श्री विनोद मिश्र (जौनपुर) ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। इस अवसर पर राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव एवं सांसद प्रो. रामगोपाल यादव भी उपस्थित थे।

वहीं 1 अक्टूबर को सपा कार्यालय में श्री अखिलेश यादव की उपस्थिति में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी उत्तर प्रदेश ने समाजवादी पार्टी को अपना बिना शर्त समर्थन देने और जन परिवर्तन दल ने सपा में विलय करने की भी घोषणा की। इस अवसर पर बलरामपुर के पूर्व सांसद श्री रिजवान जहीर, तुलसीपुर की पूर्व प्रत्याशी जेबा रिजवान, उरई जालौन के पूर्व विधायक श्री विनोद चतुर्वेदी, कांग्रेस के राठ हमीरपुर से पूर्व विधायक श्री गयादीन अनुरागी, बसपा के घाटमपुर कानपुर के पूर्व विधायक श्री राम प्रकाश कुशवाहा समाजवादी पार्टी में शामिल हो गये।

भाजपा छोड़कर पूर्व सांसद हमीरपुर स्वामी ब्रह्मानंद जी के प्रपौत्र श्री चंद्र नारायण सिंह लोधी तथा प्रपौत्री श्रीमती चंद्रकान्ता राजपूत, दलित महासभा के प्रदेश अध्यक्ष श्री राहुल भारती, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अपना दल (ब) डॉ. ओंकार सिंह पटेल, भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के डॉ. एच.एन. पटेल तथा जिलाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा भाजपा उप्र डॉ. अरूण कुमार मौर्या भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं।

19 अक्टूबर को जनपद लखीमपुर के श्री ज्ञान बाजपेयी और जालौन के श्री सुदामा दीक्षित ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता

ग्रहण की।श्री ज्ञान बाजपेयी तीन बार नगर पालिका अध्यक्ष बने थे। सन् 2012 से 2017 के विधानसभा चुनावों में प्रत्याशी रहे तथा श्री सुदामा दीक्षित जालौन के माधोगढ़ में दो बार ब्लाक प्रमुख रहे।जनपद देवरिया के श्री शैलेश कुमार त्रिपाठी निवासी ग्राम इजरही माफी पोस्ट बरयार भाजपा छोड़कर तथा श्री मनमोहन मिश्रा निवासी उमानगर देवरिया बसपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए।

सपा में शामिल होनेवालों में बसपा के श्री उदय लाल मौर्य, पूर्व विधायक मधुसूदन कुशवाहा पूर्व प्रत्याशी बांदा, राम सेवक पाल एडवोकेट प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय पाल महासभा, विजय कुशवाहा कुशवाहा महासभा, डाॅ विमलेश गौतम पूर्व विधायक लखीमपुरखीरी, प्रेम सिंह कुशवाहा कानपुर, रोहित यादव प्रधान सहित महोबा, बांदा, बुंदेलखण्ड के सैकड़ों लोग प्रमुख हैं।

सर्वश्री अतुल आक्रोश दूबे, दिलीप मिश्रा, सुनील तिवारी एडवोकेट सहित इटावा, आगरा, औरैया के सैकड़ों कर्मचारी संयुक्त परिषद के पदाधिकारियों ने भी समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली। राष्ट्रीय कायस्थ महापरिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मयंक श्रीवास्तव अपने समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं।

समाजवादी पार्टी में बड़ी संख्या में शामिल विभिन्न दलों एवं संगठनों के नेताओं का स्वागत करते हुए श्री अखिलेश यादव ने उम्मीद जताई कि इनसे समाजवादी पार्टी को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि लोग लगातार समाजवादी पार्टी से जुड़ रहें है। सभी जाति वर्ग के लोग आगे आकर इस लड़ाई में समाजवादी पार्टी का साथ दे रहे है। भाजपा ने जनता को धोखा के अलावा कुछ नहीं दिया हैं आने वाले समय में सब साथी मिलकर सपा सरकार बनाएंगे। हम भरोसा दिलाते हैं कि बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर के बनाए संविधान और डॉ. राममनोहर लोहिया के रास्ते पर चलकर समाज और देश को खुशहाली के रास्ते पर ले जाने का काम करेंगे।

श्रद्धांजलि

सुखदेव राजभर

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने प्रदेश के वरिष्ठ राजनेता एवं उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय सुखदेव राजभर जी के निवास स्थान पर पहुंचकर उनके पार्थिव शरीर पर श्रद्धासुमन अर्पित कर शोक संतप्त परिवार से संवेदना जताई। श्री सुखदेव राजभर का 18 अक्टूबर को लखनऊ में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था।

श्री अखिलेश यादव ने कहा कि श्री सुखदेव राजभर जी के निधन से प्रदेश को अपूरणीय क्षति हुई है। सामाजिक न्याय को समर्पित उनका राजनीतिक जीवन सदैव प्रेरणा देता रहेगा। एक गरीब परिवार से संबंध रखते हुए वकालत और सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने वाले राजभर जी को नमन।

उल्लेखनीय है कि श्री राजभर ने सार्वजनिक रूप से श्री अखिलेश यादव की प्रशंसा करते हुए कहा था कि यूपी का पिछड़ा-वंचित समाज अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी सरकार बनाने के लिए जी-जान से जुट गया है। विगत 29 अगस्त को श्री राजभर का हालचाल लेने श्री अखिलेश यादव उनके लखनऊ स्थित आवास पर भी गए थे।

साफ़ और बेबाक

Akhilesh Yadav

@yadavakhilesh

Socialist Leader of India. Chief Minister of UP (2012 - 2017)

Akhilesh Yadav
@yadavakhilesh

इस बार सरकार पश्चिमी उप्र बनाएगा

किसानों की एकता और एकजुटता के सामने किसान आंदोलन को तोड़नेवाले ख़ुद टूट गये हैं।

किसान-शहादत ज़िंदाबाद!

Translate Tweet

Akhilesh Yadav
@yadavakhilesh

"हमें अपना कार्य करते रहना चाहिए, वहाँ भी जहां इसकी कद्र न हो"

महान स्वतंत्रता सेनानी, प्रखर समाजवादी विचारक एवं ओजस्वी वक्ता डॉ. राम मनोहर लोहिया जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धापूर्वक नमन एवं श्रद्धांजलि।

Translate Tweet

Akhilesh Yadav
@yadavakhilesh

#बाइस_में_बाइसकिल

Akhilesh Yadav
@yadavakhilesh

श्री लालजी वर्मा जी और श्री राम अचल राजभर जी से शिष्टाचार भेंट।

Translate Tweet

Akhilesh Yadav
@yadavakhilesh

सपा सरकार की तुलना में उप्र की भाजपा सरकार के समय में उप्र में प्रति व्यक्ति आय घटकर अब लगभग एक तिहाई रह गयी है। महँगाई कई गुनी लेकिन कमाई व बैंक में बचत ब्याज दर आधी रह गयी है। अच्छे दिन का वादा करनेवाले भाजपाई बताएं कि इस आर्थिक बदहाली में आम आदमी करे तो करे क्या।

#भाजपा_ख़त्म

Akhilesh Yadav
@yadavakhilesh

गोरखपुर में भाजपा सरकार की हिंसक प्रवृति के शिकार हुए कानपुर के युवा व्यापारी स्व. मनीष गुप्ता जी के शोक संतप्त परिवार के साथ आज दुख साझा किया।

इस हत्याकांड की उच्च स्तरीय न्यायिक जाँच हो और परिवार को यथोचित न्याय मिले।

इस हत्या के लिए उप्र का शासन-प्रशासन बराबर का दोषी है।

Translate Tweet

Akhilesh Yadav
@yadavakhilesh

उप्र की भाजपा सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार भी एक छलावा है। साढ़े चार साल जिनका हक़ मारा आज उनको प्रतिनिधित्व देने का नाटक रचा जा रहा है। जब तक नये मंत्रियों के नामों की पट्टी का रंग सूखेगा तब तक तो 2022 चुनाव की आचार संहिता लागू हो जाएगी।

भाजपाई नाटक का समापन अंक शुरू हो गया है।

Translate Tweet

Following

Akhilesh Yadav
@yadavakhilesh

ये नहीं गिरफ़्तारी है
ये तो जंग हमारी है!

आज अहंकारी भाजपा का विकृत रूप व चेहरा जनता के सामने किसानों की हत्या के रूप में आया है। भाजपा के समर्थकों के सिर भी शर्म से झुक गये हैं। अन्नदाता के हत्यारों का साथ देने का अपराधबोध उनके गले से एक निवाला भी नीचे उतरने नहीं दे रहा है।

Translate Tweet

Akhilesh Yadav
@yadavakhilesh

उप्र के हर निवासी और परिवार के सुख, चैन, कल्याण के लिए और नव उप्र के निर्माण और विकास के लिए... 'समाजवादी रथ यात्रा' को ऐतिहासिक रूप से सफल बनाएं!

हर एक उप्रवासी, सामाजिक कार्यकर्ता, सपा के समर्थक, नेतागण, पदाधिकारी और कार्यकर्ता से इसमें शामिल होने की अपील है।

#बाइस_में_बाइसिकल

Akhilesh Yadav
@yadavakhilesh

भाजपा सरकार ने लम्बे समय से चली आ रही 'ओबीसी' समाज की गणना की माँग को ठुकरा कर साबित कर दिया है कि वो 'अन्य पिछड़ा वर्ग' को गिनना नहीं चाहती है क्योंकि वो ओबीसी को जनसंख्या के अनुपात में उनका हक़ नहीं देना चाहती है।

धन-बल की समर्थक भाजपा शुरू से ही सामाजिक न्याय की विरोधी है।

Akhilesh Yadav
@yadavakhilesh

उप्र के शासन-प्रशासन ने लखीमपुर के नामज़द आरोपी को समन भेजने की जो औपचारिक कार्रवाई की है उससे जनाक्रोश और बढ़ गया है। 'लखीमपुर हत्याकांड' के बाद जिस तरह पूरे देश, विशेषकर उप्र में किसानों के बीच भावात्मक एकता जन्मी है वो अभूतपूर्व है।

गाँवों में भाजपा के झंडे उतर गये हैं।

Translate Tweet

Akhilesh Yadav
@yadavakhilesh

पूर्वांचल की ग़रीबी व पिछड़ेपन को दूर करने के लिए जिस समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का शिलान्यास किया था उसके पूरा होने की ख़ुशी है, पर ये दुख भी है कि भाजपा ने इसके मूल स्वरूप व गुणवत्ता से समझौता किया है।

भाजपा विकास के रास्ते बनाना नहीं जानती है।

#सपा_का_काम_जनता_के_नाम

Translate Tweet

Akhilesh Yadav
@yadavakhilesh

ये इतिहास में पढ़ाया जाता रहा है कि सम्राट मिहिर भोज गुर्जर-प्रतिहार थे पर भाजपाइयों ने उनकी जाति ही बदल दी है। निंदनीय!

छलवश भाजपा स्थापित ऐतिहासिक तथ्यों से जान-बूझकर छेड़छाड़ व सामाजिक विघटन करके किसी एक पक्ष को अपनी तरफ़ करती रही है।

हम हर समाज के मान-सम्मान के साथ हैं!

पंजीकृत डाक पंजीकरण संख्या GPO/LW/NP-300/2021-2023 कुल पृष्ठ : 76 डिस्पैच तिथि : 15, 16, 17

निजीकरण की कुल्हाड़ी
आरक्षण पर पड़ेगी भारी

समाजवादी पार्टी

#2022
आ रहे हैं
अखिलेश